घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 241- गुरूवार 02- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

नए सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने कार्यभार संभालने के बाद पिता और छोटे भाई को किया सैल्यूट

हमारा सबसे बड़ा मकसद स्वदेशी तरीकों का इस्तेमाल करके युद्ध जीतना होगा : आर्मी चीफ

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। नए सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को पहला गार्ड ऑफ ऑनर साउथ ब्लॉक लॉन्स में दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ (सेवानिवृत्त) और छोटे भाई रियर एडमिरल रविनीश सेठ को सैल्यूट किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मकसद स्वदेशी तरीकों का इस्तेमाल करके युद्ध जीतना होगा। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के बारे में लगातार विजिलेंस बनाए रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का असरदार तरीके से मुकाबला करने के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस का हाई लेवल बनाए रखेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला के पुराने स्टूडेंट जनरल सेठ आर्मड कोर के पहले ऑफिसर हैं, जो 1997 में 20 लांसर्स के जनरल शंकर रॉय चौधरी के रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने हैं। वे एक जाने-माने सैन्य परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ 1997 में आर्मी के एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे, जब नए आर्मी चीफ खुद कैप्टन थे। उनके भाई रियर एडमिरल रविनीश सेठ भारतीय नौसेना में फ्लैग ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। जनरल सेठ को सैन्य क्षेत्र में जमीनी और ऑपरेशन पर फोकस करने वाले कमांडर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने उसी भोपाल-बेस्ड 21 स्ट्राइक कोर को कमांड किया है,

जिसे कभी उनके पिता लीड करते थे। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना को तकनीक से चलने वाली भविष्य के लिए तैयार फोर्स बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करना और 'ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट' के आइडियल्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराना 'गर्व और विनम्रता' की बात है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें नए जोश और पक्के इरादे के साथ सेना की आधुनिकता को आगे बढ़ाना होगा। हमारा मकसद प्रौद्योगिकी समर्थित भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना है, जो हर तरह से सशक्त हो और कई डोमेन में काम करने में सक्षम हो। इन मकसदों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इनोवेशन हमारी सोच, ऑपरेशनल तरीकों और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा होगा। इसके अलावा हम बदलते युद्ध क्षेत्र के हिसाब से ढलने के लिए जरूरी बदलाव लागू करेंगे। आर्मी चीफ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत अपने पहले के आर्मी चीफ के बारे में कहा कि उनके विजन और लीडरशिप में भारतीय सेना मजबूत और भरोसेमंद फोर्स के तौर पर विकसित हुई है। भारतीय सेना की ऑपरेशनल प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हम वायु सेना और नौसेना के साथ पूरा तालमेल बनाए रखेंगे। यह तरीका हमें 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने संभाला 51वें वायु सेना उप प्रमुख का कार्यभार

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पूर्व चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बुधवार को एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह लेते हुए 51वें वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद संभाला। एयर मार्शल कपूर वायु सेना में लगभग चार दशकों की शानदार सेवा के बाद 30 जून को रिटायर हुए। उनकी नियुक्ति ऐसे अहम समय पर हुई है, जब भारतीय वायु सेना अपने आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पहली बार 15 मई 2023 को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। एयर मार्शल एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होने के साथ-साथ एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी हैं। उन्हें मिग-21, मिग-29 और मिराज-2000 जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव भी है। पिछले 23 सालों से आशुतोष दीक्षित वायुसेना का हिस्सा रहे हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में दीक्षित ने 20 से अधिक प्रकार के विमानों पर 3300 घंटे की उड़ान भरी है।

बड़ा हादसा : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ंत के बाद बस में लगी आग

8 लोगों की मौत,29 घायल

दौसा,01 जुलाई 2026। राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा घटित हुआ। कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ के पास जीरो प्वाइंट पर ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में जा भिड़ी, इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है,जबकि 29 यात्री घायल हुए हैं। हादसा इतना भयावह था कि एक्सप्रेसवे पर चारों ओर चीख-पुकार मच गई और सड़क खून से लाल हो गई। कई शवों के चिथड़े घटनास्थल पर बिखरे मिले। पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज दौसा जिला अस्पताल में जारी है। इनमें से 9 घायलों की पहचान भी हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। दौसा एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार ने बताया कि घटनाक्रम रात करीब 3 बजे के आसपास का है। हादसे में अब तक 6 लोगों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जा चुका है। मामुली घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि घायलों को अभी मृतकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। एडिशनल एसपी ने बताया कि बस में 39 से अधिक सवारियां होने का

अनुमान लगाया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे के दौरान आगे चल ट्रेलर का चालक और खलासी भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार तड़के करीब 3 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। बस में फंसे 6 यात्रियों की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य यात्रियों ने सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं, दौसा की जिला कलेक्टर डॉ। सौम्या झा का कहना है कि बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी, तभी सुबह करीब 3:15 या 3:30 बजे जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। करीब 24 या 25 लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे और उन्हें बचा लिया गया। वे अभी ठीक हैं। कुल हताहतों की संख्या के बारे में हम इस समय केवल अनुमानित आंकड़ा ही बता सकते हैं,अंतिम संख्या मिलना बाकी है।

नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए की कटौती का किया ऐलान

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन वितरक कंपनी नायरा एनर्जी ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती कंपनी के देशभर में मौजूद रिटेल नेटवर्क पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस कटौती की वजह मध्य पूर्व में तनाव कम होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होना है। हालांकि,वैल्यू-एडेड टैक्स (वेट) और स्थानीय टैक्स के चलते रिटेल ईंधन की कीमतें राज्य-दर-राज्य अलग-अलग हो सकती हैं। अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध को लेकर शांति वार्ता होने से मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव कम हो गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड का दाम पिछले एक महीने में करीब 23 प्रतिशत कम हो गया है, मौजूदा समय में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 73.21

डॉलर प्रति बैरल पर है। वहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमतों में भी बीते एक महीने में करीब 25 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई है। इससे डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स का दाम घटकर 70 डॉलर प्रति बैरल के नीचे 69.73 डॉलर प्रति बैरल पर गया है। हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दिल्ली में पेट्रोल का दाम 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, तेल वितरक कंपनियों ने एक जुलाई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 183.50 रुपए घटकर 2,930 रुपए हो गया है, जो कि पहले 3,113.50 रुपए था। हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसे 942 रुपए पर स्थिर रखा गया है।

असम के बराक में 13 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त छह तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी,01जुलाई 2026। असम पुलिस ने बराक घाटी के श्रीभूमि और कछार जिलों में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कहा कि मादक पदार्थ तस्करों का दावा था, यह कारोबार है,लेकिन असम पुलिस का स्पष्ट जवाब था, असम में नहीं। पुलिस ने अभियान के दौरान 49,800 याबा टैबलेट और 535 ग्राम हेरोइन बरामद की।

जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के बजाय सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वैध आजीविका अपनाएं। उन्होंने राज्य सरकार के असम अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश

टीवीके का दावा...15 विधायकों का एक साथ इस्तीफा कराने 35 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश...

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के विधायकों को 35 करोड़ रुपए का लालच देकर राज्य सरकार को गिराने की कथित साजिश का दावा किया गया है। राज्य के खुफिया विभाग ने कहा है कि इस योजना को समय रहते नाकाम कर दिया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, साजिश के तहत टीवीके के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार को संकट में डालने की तैयारी थी। इसी बीच ऊथंगुरै से टीवीके विधायक डॉ. एन. इलैयाराजा ने आरोप लगाया कि उन्हें स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने के बदले 35 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। शिकायत के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की और चेन्नई की एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े तीन लोगों (तिरुनावुक्करासु, नरेष और त्यागराजन) को गिरफ्तार किया। जांच में उनके छ्रब्ध विधायक सेंथिल बालाजी से संबंध होने की जानकारी मिली है।

35 करोड़ की पेशकश की गई थी : 29 जून को विधायक इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि थिरुनावुक्करासु नाम के व्यक्ति ने खुद को एक सर्वे एजेंसी का प्रमुख बताकर उनसे फोन पर

संपर्क किया। आरोपी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और उनसे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट देने को कहा। इसके बदले में उसने 35 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। विधायक ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने बातचीत का खुलासा करने पर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

हमारे विधायकों से संपर्क में हैं डीएमके नेता : तमिलनाडु के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने डीएमके पर एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी के पलानीस्वामी के साथ मिलकर विजय के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीवीके के कई विधायकों को दल-बदल के लिए पैसे की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा- डप्पाडी पलानीस्वामी और अन्य लोग गुपचुप तरीकों से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं।

एमके स्टालिन और उदयनिधि के इशारे पर काम करते हुए सेंथिल बालाजी जैसे डीएमके के प्रमुख नेता हमारे कई विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। वे उन्हें 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई विधायक नहीं है, जिससे उन्होंने संपर्क न किया हो।

दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग,तीन लोग जिंदा जले

आंध्र प्रदेश,01 जुलाई 2026। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्रतिपाडु मंडल में बोयापालेम के पास एक ट्रक के सामने से आ रहे दूसरे वाहन से टकराने के बाद तीन लोगों की

जलकर मौत हो गई। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे बोयापालेम गांव में हुआ। नरहरी इंस्पेक्टर के अनुसार, एक ट्रक कुरनूल से गुंटूर की ओर और दूसरी गुंटूर से चिलकलुरिपेट की ओर कागज का सामान लेकर जा रही थी। तभी बोयापालेम के पास नेशनल हाईवे-16 पर आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार,आग में दो ड्राइवर और एक हेल्पर जिंदा जल गए। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे बोयापालेम गांव में हुआ। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया,क्योंकि दोनों लॉरी पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थीं। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत कार्य शुरू किया,जबकि भीड़ कम करने के लिए गाड़ियों की आवाजाही सर्विस रोड से डायवर्ट कर दी गई। फायरफाइटर भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का काम किया।

भारत का विदेशी कर्ज 72 लाख करोड़ के पार,आरबीआई रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन इसी बीच आरबीआई के ताजा आंकड़ों ने देश की बाहरी देनदारियों की नई तस्वीर पेश की है।

भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 762.8 अरब डॉलर यानी करीब 72.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मार्च 2026 के आखिर तक भारत का विदेशी कर्ज एक साल पहले के मुकाबले 26.3 अरब डॉलर बढ़ा है। हालांकि इस बढ़ोतरी की असली तस्वीर इससे भी बड़ी है। आरबीआई के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने विदेशी कर्ज की वास्तविक बढ़ोतरी को आंशिक रूप से छिपा दिया। अगर वैल्यूएशन इफेक्ट को हटा दिया जाए तो विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी 26.3 अरब डॉलर नहीं, करीब 51 अरब डॉलर होती। यानी डॉलर के मुकाबले अन्य प्रमुख मुद्राओं के कमजोर पड़ने से उन मुद्राओं में लिए गए कर्ज की डॉलर में गणना कम हुई।

संगठित गिरोह का भंडाफोड़...9 किलो सोना और 42 किलो चांदी जब्त,8 गिरफ्तार

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में विदेशी मूल का लगभग 9 किलो सोना, 42 किलो चांदी, 700 ग्राम सोने के गहने, 8.15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा और 26.67 लाख रुपये भारतीय मुद्रा बरामद की गई है। कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई ने बुधवार को बताया कि गिरोह पूर्वोत्तर राज्यों से दिल्ली तक अलग-अलग ट्रेनों से तस्करी कर सोना लाता था। तस्करों ने दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में सोना गलाने की अवैध इकाई भी चला रखी थी। 26 जून को डीआरआई अधिकारियों ने पश्चिम

बंगाल के न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन और बिहार के मंसी जंक्शन पर दो तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से करीब 2 किलो सोना मिला। इसी दिन दिल्ली में भी दो लोगों को 1.2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया।

इन गिरफ्तारियों के बाद दिल्ली में अवैध सोना गलाने की इकाई का पता चला। उसी दिन एक अन्य कार्रवाई में डीआरआई ने एक महिला तस्कर को पकड़ा, जो मिजोरम के सैरांग से कोलकाता जा रही थी। उसके पास से कमरबंद में छिपाकर रखी गई सोने की 20 ईंटें मिलीं, जिनका वजन 3.3 किलो था। चेन्नई में डीआरआई ने घरेलू हवाई मालवाहक सेवा के जरिए विदेशी मुद्रा की तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा। यहां से 7,58,500 अमेरिकी डॉलर और 35 लाख थाई बाहट बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 8.15 करोड़ रुपये है। जांच में पता चला कि यह विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजी जा रही थी और इसका इस्तेमाल सोना-चांदी की तस्करी के लिए किया जा रहा था। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर डीआरआई ने एक व्यक्ति को दुबई से लौटते समय पकड़ा, जिसके पास से 1.8 किलो सोना मिला। उसके घर से 42 किलो चांदी, 700 ग्राम सोने के गहने और 26.67 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए। डीआरआई ने कहा कि यह कार्रवाई साबित करती है कि विदेशी मुद्रा की अवैध खरीद-फरोख्त और उसका बाहर भेजा जाना सीधे तौर पर सोना-चांदी की तस्करी से जुड़ा हुआ है। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आठ लोगों से पूछताछ जारी है और आगे की जांच में और खुलासे हो सकते हैं।

महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे,भड़कीं सांसद

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा का दावा है कि नादिया के कालीगंज स्थित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में उनके ऊपर अंडे और बैंगन फेंके गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थक लगातार पार्टी कार्यालय की तीसरी मंजिल को निशाना बनाकर अंडे और बैंगन फेंक रहे थे। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद रहने के बावजूद उसने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की और मूकदर्शक बनी रही। फेसबुक लाइव में उन्होंने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था बनाए

रखने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय पुलिस केवल तमाशा देखती रही। हालांकि,इस घटना पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं,पुलिस ने भी सार्वजनिक रूप से इस मामले में कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों या विभिन्न मामलों के आरोपियों पर अंडे फेंकने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है।

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने वाला विधेयक को जल्द मंजूरी दे सकती है जेपीसी

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है। फिलहाल ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास है,जो इसे सत्र शुरू होने से पहले मंजूरी दे सकती है। इस विधेयक में गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखे जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि जेपीसी ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक,जेपीसी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाए जाने के प्रावधान को बरकरार रखा है।

बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

पटना,01 जुलाई 2026। बिहार विधान परिषद के एनेक्सी भवन में बुधवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 10 नवनिर्वाचित नेताओं ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। समारोह में राज्य सरकार और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण की शुरुआत भोजपुरी अभिनेता एवं नवनिर्वाचित विधान पार्षद पवन सिंह से हुई। उन्होंने सबसे पहले एमएलसी पद की शपथ ग्रहण की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री

निशांत कुमार, संजय मयूख, सुनील कुमार सिंह सहित सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने क्रमवार शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और तेजस्वी यादव मंच पर एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आए। उल्लेखनीय है कि लगभग 20 दिन पहले बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चार, जनता दल (यूनाइटेड) के चार, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

संपादकीय

कसी जाए मंत्रियों के चयन की कसौटी

इन दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल-विस्तार की चर्चा जोरों पर है। माना जाता है कि अगले कुछ दिनों में मोदी सरकार अपने इस तीसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ फेरबदल भी कर सकती है। इसका एक कारण तो यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के दो सदस्य पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बन गए हैं। दूसरा कारण दो मंत्रियों रवनीत सिंह बिट्टू और जार्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होना है। इनमें कुरियन ने तो त्यागपत्र दे दिया है और वह मंजूर भी हो गया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने अभी त्यागपत्र नहीं दिया, लेकिन यह कहा है कि अब वे अपना ध्यान पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रित करेंगे।

मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार-फेरबदल का एक संभावित आधार आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों का भाजपा में शामिल होना,शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के छह लोकसभा सदस्यों का एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होकर सत्तापक्ष का संख्याबल बढ़ाना भी है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संख्याबल इसलिए भी बढ़ गया है,क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सदस्य ममता बनर्जी से बगावत करके एक गुमनाम से दल नेशनल सिटिजंस पार्टी आफ इंडिया में शामिल होकर इस गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। इसी के साथ यह पार्टी राजग का सबसे बड़ा घटक बन गई है। उसने संख्याबल के मामले में तेलुगु देसम पार्टी, शिवसेना (शिंदे) और जनता दल-यू को भी पीछे छोड़ दिया है।

मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार-फेरबदल का एक अन्य कारण यह गिनाया जा रहा है कि अगले वर्ष सात राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। इस सबके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल-विस्तार की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि मंत्रियों के लगभग दो वर्ष के कामकाज की समीक्षा संभावित थी। इस समीक्षा के तहत मंत्री पदोन्नत या पदावनत हो सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन आसार इसलिए अधिक हैं, क्योंकि भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को भी अपनी टीम गठित करनी है और इसके तहत कुछ नेता संगठन से सरकार में और कुछ सरकार से संगठन में जा सकते हैं। चूंकि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होता रहा है, इसलिए इस बार भी ऐसा होना संभावित माना जा रहा है। अतीत में जब भी ऐसा हुआ है,तब कुछ केंद्रीय मंत्रियों की अप्रत्याशित रूप से छुट्टी हुई है और कुछ ऐसे चकित करने वाले चेहरे मोदी सरकार का हिस्सा बने,जिनके बारे में शायद ही किसी ने अनुमान लगाया हो।

यह मोदी सरकार की विशेषता है कि वह अपने फैसलों से चौंकाती है और ऐसे फैसले केवल मंत्रियों के चयन के मामले में ही नहीं होते रहे। मुख्यमंत्रियों के चयन के मामले में भी यह देखने को मिलता रहा है। आखिर किसने सोचा था कि राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे? ऐसा ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मामले में भी हुआ। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,लोकसभा अध्यक्ष समेत अन्य अनेक पदों पर ऐसे लोग आए,जिनके बारे में किसी को भान नहीं था। आम लोगों और यहां तक कि राजनीतिक पंडितों के अनुमान से परे जाकर अप्रत्याशित फैसले लेना मोदी सरकार की एक खासियत अवश्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसका हर चौंकाने वाला फैसला सटीक यानी मास्टर स्ट्रोक ही होता हो।

यह सही है कि कोई भी सरकार हो, उसके प्रमुख को अपने मंत्रियों का चयन करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा करते समय भी योग्यता को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए,क्योंकि कोई सरकार अपने मंत्रियों के कामकाज के आधार पर ही जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में समर्थ हो सकती है। लगभग प्रत्येक सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं,जो केवल सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों में संतुलन बैठाने का काम करते हैं,लेकिन जब ऐसा करते समय योग्यता और दक्षता को सर्वोच्च वरीयता नहीं दी जाती, तो इसके दुष्परिणाम संबंधित सरकार के साथ जनता को भी भोगने पड़ते हैं। किसी के लिए भी यह कहना कठिन होगा कि मोदी सरकार के सभी मंत्री कसौटी पर खरे साबित उतरे हैं।

एक सक्षम सरकार को अपने मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा सतत करनी चाहिए,न कि साल-दो साल के अंतराल पर। इसी तरह इसका कोई औचित्य नहीं कि मंत्रियों को विधानसभा चुनावों का प्रभारी बना दिया जाए। यदि वे संगठन के लिए उपयुक्त हैं तो फिर उन्हें संगठन में स्थान दिया जाना चाहिए,न कि मंत्रिमंडल में। पिछले कुछ समय से यह एक चलन सा बन गया है कि जब भी कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं तो महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव प्रभारी या सह-प्रभारी बना दिया जाता है। हाल के विधानसभा चुनावों में भी यह देखने को मिला। क्या केंद्रीय मंत्रियों के पास इतना कम काम होता है कि वे अपने मंत्रालय का प्रभार छोड़कर पार्टी को विधानसभा चुनाव जिताने में लग जाएं?

जल चिकित्सा से मिलती है सभी रोगों से मुक्ति

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम
मध्यप्रदेश

मनुष्य के शरीर का निर्माण आकाश, वायु,अग्नि, जल और पृथ्वी पंच तत्व से मिल कर हुआ हैं। मानव शरीर की उत्पत्ति में पंचतत्वों के योग का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं- क्षितिज पावक जल गगन समीरा, पंचतत्व रचित अधम शरीरा।। यह सृष्टि पँच तत्वों के समयोग का परिणाम है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र के बीच जीवन और स्वास्थ्य के पुष्प पल्लवित हैं और भगवान् मोक्ष के कारक है। भगवान् वाचक शब्द के अक्षरों का विश्लेषण करें तो (भ) अर्थात भूमि (पृथ्वी),(ग)अर्थात गगन (आकाश), (व) अर्थात वायु,(अ) अर्थात अग्नि तथा (न) अर्थात नीर (जल) ये पँच तत्वों की ओर संकेत करता है,इसलिए मनुष्य को और इन पंचतत्व को ब्रम्ह माना है। इन पाँच तत्वों में एक प्रधान तत्व जल है जो प्रकृति के साथ-साथ मानव शरीर में प्रमुखता से विद्यमान रहता है। शरीर चिकित्सकों के अनुसार मानव शरीर का 70 प्रतिशत भाग जल तत्व ही है। शरीर में इस जल तत्व का समयोग स्वास्थ्य एवं इस तत्व की विषम अवस्था रोगों को उत्पन्न करती है,वहीं यह जल तत्व इस शरीर में व्याप्त हर प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों को समूल नाश करने में सक्षम है। बशर्ते किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से इसकी सभी विधिया वांछित रोगों के उपचार हेतु सोने में सुहाना साबित हों सकेगी । सृष्टि की रचना करने वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी इन पंचतत्वों की उत्पत्ति को भी समझना आवश्यक है। ऋषि मुनियों द्वारा रचित ग्रंथो व वेदों में व्याख्या मिलती है कि जल से पृथ्वी,पृथ्वी से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि पैदा हुई, यह शरीर जब मुर्दा हो जाता है तब इस मुर्दाशरीर में जल नहीं रहता और जड चेतन जो आकार रूपवान है वह सब जल का स्वरूप है और जल का स्वरूप सिद्धान्त अनुमानित होता है और आदि में सब की उत्पत्ति का कारण जल होता है। मनुष्य शरीर और जल एक दुसरे के पूरक है,मनुष्य देह को जल के प्रयोग पर विचार करना चाहिए,जैसा की पहले ही तुलसीदास जी की चोपाई का उल्लेख हैं, कि क्षिति जल,पावक,गगन,समीरा इन्हीं पांचों तत्वोंसे हमारी देह बनी है। इसलिये जल नहीं हो,तो हमारी देह कायम नहीं रह सकती। साधारणतः हमारे देश में सब लोग इस जलको किस तरह काम में लाते हैं, इसी को देखना चाहिये।

पृथ्वी पर जीवन का प्रारम्भ जल तत्व में ही हुआ। सर्वप्रथम जलीय जीवों की उत्पत्ति के बाद चलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। यह जल तत्व जलीय एवं

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

स्थलीय दोनों ही प्रकार के जीवों के लिए समान रुप से आवश्यक तत्व है। इस जल तत्व की महिमा का वर्णन प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिको तक ने की है। अनेक वैदिक कर्मकाण्डों में जल को अमृत रुप मानक जल से प्रक्षालन, आचमन एवं संकल्प धारण आदि कियाओं का उपदेश किया गया है। वैदिक दैनिक अग्निहोत्र में दाहिनी हाथ की हथेली में जल लेकर निम्न मंत्र से तीन बार आचमन करने का विधान है-

ओ3म् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा।
ओ3म् अमृतापिधानमसि स्वाहा।
ओ3म् सत्यं यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा।।
(तैत्तिरीय अरण्यक)

अर्थात हे अविनाशी परमेश्वर । आप सबके रक्षक हैं। आन्तरिक एवं बाह्य दुखों से हमारी रक्षा कीजिए। हे परम दाता प्रभों। हम आपकी कृपा से सच्चा ज्ञान,विमल कीर्ति,भौतिक सम्पन्नता एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। हम आपके उदार स्वाभाव से परिचित हैं और अपने साथियों को परिचित कराते हैं।

पृथ्वी पर जल तत्व का अपना एक विशिष्ट स्थान है और इसके गुण के कारण ही जल को परम ओषधि की मान्यता मिली है और जल को अमृत तक कहा गया है । स्थूलता के आधार पर जल तत्व दूसरा स्थूलतम् तत्व है जिसे सामान्य भाषा में पानी, वारि, नीर, तोय,अम्बु,सलिल,आप,उदक तथा अमृत आदि नामों से जाना जाता है। यह जल तत्व पृथ्वी पर प्रर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वी का 70 प्रतिशत जल तत्व से निमग्न है। जिस प्रकार पृथ्वी का 70 प्रतिशत भाग जल तत्व से परिपूर्ण है ठीक उसी प्रकार मानव शरीर का भी 70 प्रतिशत भाग जल तत्व ही है। यह जल तत्व जीवधारियों के जीवन का आधार होता है। इस तत्व के अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मनुष्य के जीवन का आधार भी यह जल तत्व ही है। इन तत्व के द्वारा मनुष्य विभिन्न दैनिक एवं निमेतिक कार्यों को करने में सक्षम होता है। इस तत्व के अभाव में मनुष्य के दैनिक एवं निमैतिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र में जल तत्व प्रमुख रुप से उपस्थित तत्व है। यह तंत्र मकड़ी के जाले के समान सम्पूर्ण शरीर में फैला है जिसके अन्तर्गत विभिन्न तंत्रिकाएं जल तत्व के माध्यम से बाह्य वातावरण से संवेदनाओं एवं प्रेरणाओं को ग्रहण करती है। जल चिकित्सा का तात्पर्य जल के प्रयोग से रोग निवारण तथा आरोग्य प्राप्त कराना है। इसके लिए अलग-अलग रोगों के अनुसार अलग-अलग तापमान के जल को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जिसके प्रमुख दो भेद है :

1. आन्तरिक प्रयोग 2. बाह्यप्रयोग, इसमें बाहरी प्रयोग में स्नान,उत्सर्जन, विसर्जन शरीर शुद्धी आदि शामिल है। जल तत्व के अभाव में तंत्रिकाओं की कार्यकुशलता एवं क्षमता कम हो जाती है। मानव मस्तिष्क में भी जल तत्व प्रमुख रुप से उपस्थित तत्व है। शरीर में जल तत्व के अभाव में विभिन्न प्रकार मस्तिष्क संम्बन्धी रोगों की उत्पत्ति होती है। जल चिकित्सा के अन्तर्गत ठण्डे जल के प्रयोग से तंत्रिकाओं को बल मिलता है जबकि गर्म जल के प्रयोग से रक्त संचार तीव होने से तंत्रिकाओं की कियाशीलता बढ़ती है। विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं से सम्बन्धित रोगों में जल चिकित्सा का प्रयोग विशेष रुप से लाभकारी प्रभाव रखती है। मस्तिक विकारों में भी जल चिकित्सा के प्रयोग से लाभमिलता है।

वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5,पीएम 10,पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही,लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता,लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा।

दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है,जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है,दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है,आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई,एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन,नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा,चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत,तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं,उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था,वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए,आवास चाहिए,उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा,बल्कि जल,मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। विकास की यह दिशा अंततः मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है।

ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन,अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं,ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी,वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा।

समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल,खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन भी प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा।

सच्ची मोहब्बत या टाइम-पास

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,
बिहार

आज के दौर में यह पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि सामने वाला आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या फिर टाइम-पास। सोशल मीडिया के इस आधुनिक दौर में सब कुछ दिखावटी है इसलिए डर लगता है मुझे, कि कहीं मैं किसी से मोहब्बत न कर बैठूँ या फिर वो मुझे मोहब्बत के नाम पर छल न दे। क्योंकि अक्सर जब किसी लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो उसे लगता है कि उसे उसका हमसफ़र यानी जीवन साथी मिल गया है। वो सोचती है कि यही वो इंसान है जो उसके सुख-दुःख में साथ देगा,उम्र भर उसका हाथ थामे रखेगा और उसकी हर समस्या का समाधान बनेगा। लड़की का दिल उम्मीदों से भर जाता है,खुली आँखों से वो सपने बुनने लगती है। लेकिन हकीकत कभी-कभी बदल जाती है। अक्सर जो हम चाहते हैं या सोचते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। जो सपने उसने खुली आँखों से देखे थे वो अधूरे रह जाते हैं और वो उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं जब उसे यह पता चलता है कि जिसे चाहा था अपनी जान से ज़्यादा वो बस उसकी भावनाओं से खेल रहा है। मोहब्बत मजाक नहीं, जिम्मेदारी होती है। ये बात कैसे समझाऊँ उसे, कि उसके बिना जीना कितना मुश्किल हो गया है। मोहब्बत में 'मैं' से पहले 'हम' आ जाता है, खुद से पहले अपने जीवनसाथी के बारे में सोचना पड़ता है। मोहब्बत में सिर्फ घूमना-फिरना,गिफ्ट देना,आई लव यू बोलना नहीं होता। मोहब्बत में तड़पना,रूठना-मनाना,उम्र भर साथ निभाना होता है। मोहब्बत में मान-

सम्मान,भरोसा,अधिकार देना होता है और सबसे ज़रूरी धैर्य होना चाहिए क्योंकि मोहब्बत जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझदारी से निभाई जाती है। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया, फिल्में और रील्स ने रिश्तों को इतना चमकदार बना दिया है कि लोग आकर्षण को ही मोहब्बत समझ लेते हैं। चैटिंग को केयर मान लेते हैं और दो महीने की बातचीत को बीस साल का साथ। और यही सोशल मीडिया वाले लोग मोहब्बत के नाम पर टाइम-पास करते हैं, अपने खाली समय को बिताते हैं। जो टाइम-पास करने वाले होते हैं वो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, वादे आसमान से भी ऊँचे करते हैं और निभाने का समय आता है तो उल्टे पाँव दौड़ते नजर आते हैं। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है लेकिन मोहब्बत के नाम पर छलना बुरी बात है। मोहब्बत तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, पर अंधी मोहब्बत ज़रूर तकलीफ देती है। आँखें खोलकर प्यार करो, दिमाग से सोचो, दिल से महसूस करो। जो इंसान वक्त माँगे, सब्र माँगे, आपकी इज्जत करे समझ जाओ वो मोहब्बत है। और जो सिर्फ वक्त ले, इज्जत न दे, वादे करके मुकर जाए वो टाइम-पास है।

आस्था की चौखट पर असुरक्षा

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार हरियाणा

भारत की सांस्कृतिक पहचान केवल उसके इतिहास,भाषाओं और परंपराओं से नहीं बनती,बल्कि उन आस्था-स्थलों से भी निर्मित होती है जिन्होंने सदियों से समाज को नैतिकता,सहअस्तित्व और सामुदायिक एकता का संदेश दिया है। मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं; वे विश्वास,संस्कृति,लोकजीवन और सामाजिक सहभागिता के जीवंत केंद्र हैं। यहां लोग केवल ईश्वर के दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने सुख-दुख साझा करने,मन की शांति पाने और जीवन के संघर्षों में आशा का संबल प्राप्त करने आते हैं। यही कारण है कि जब किसी मंदिर में चोरी होती है,तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता। यह करोड़ों लोगों की आस्था,सामाजिक विश्वास और सांस्कृतिक चेतना पर सीधा आघात होता है।

बीते कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से मंदिरों में दानपेटियां तोड़ने, नकदी चुराने,बहुमूल्य आभूषण गायब करने, प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करने और धार्मिक सामग्री की चोरी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। कई मामलों में अपराधियों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग किया,जबकि कई घटनाओं में अंदरूनी मिलीभगत की आशंका भी सामने आई। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि समाज के नैतिक मूल्यों और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी रह गई है। जिस स्थान को लोग सबसे सुरक्षित और पवित्र मानते हैं, यदि वही अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बनने लगे, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

मंदिरों में चोरी को सामान्य संपत्ति-अपराध की श्रेणी में रखकर उसकी गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। किसी दुकान,मकान या कार्यालय में चोरी आर्थिक क्षति पहुंचाती है,लेकिन मंदिर में चोरी विश्वास की जड़ों को भी कमजोर करती है। श्रद्धालु अपनी कमाई का एक हिस्सा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, सेवा और समाजहित की भावना से दान करते हैं। वे यह विश्वास रखते हैं कि उनका अर्पण धर्मार्थ कार्यों, सामाजिक सेवा और मंदिर व्यवस्था में उपयोग होगा। जब वही धन चोरी हो जाता है, तो केवल दानपेटी खाली नहीं होती, बल्कि श्रद्धालु के मन में भी संदेह और पीड़ा जन्म लेती है। यही कारण है कि मंदिरों में चोरी की घटनाएं समाज में सामान्य अपराधों की तुलना में कहीं अधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं।

ऐसी घटनाओं के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण नकद दान की परंपरा है। आज भी देश के अधिकांश मंदिरों में बड़ी मात्रा में नकद चढ़ावा आता है। अनेक छोटे और मध्यम मंदिरों में दान की गणना, सुरक्षित भंडारण और बैंक में जमा करने की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं होती। कई बार दानपेटियां लंबे समय तक नहीं खोली जातीं,जिससे उनमें बड़ी मात्रा में नकदी जमा हो जाती है। यह स्थिति अपराधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो और बड़ी मात्रा में नकद धन उपलब्ध हो, वहां अपराध की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता है। महानगरों के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे,आधुनिक अलार्म सिस्टम,रात्रि सुरक्षा, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या केवल औपचारिक रूप से स्थापित हैं। कई कैमरे खराब पड़े रहते हैं, रिकॉर्डिंग का बैकअप सुरक्षित नहीं होता और नियमित निगरानी भी नहीं की जाती। अपराधी इन कमियों का अध्ययन कर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। प्रबंधन संबंधी कमजोरियां भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। अनेक मंदिरों का संचालन पारंपरिक ढंग से होता है,जहां वित्तीय जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता के स्पष्ट मानक नहीं बने हैं। दान की गणना,लेखा-जोखा, व्यय और भंडारण की प्रक्रिया कई बार व्यवस्थित नहीं होती। जहां जवाबदेही कमजोर होती है,वहां गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मामलों में चोरी बाहरी अपराधियों द्वारा नहीं, बल्कि अंदरूनी मिलीभगत से भी की जाती है। यह स्थिति अधिक चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इससे संस्था के भीतर का विश्वास भी टूटता है।

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी इस समस्या से जुड़ी हुई हैं। बेरोजगारी, नशे की लत, कर्ज का बोझ,त्वरित धन कमाने की मानसिकता और नैतिक मूल्यों का ह्रास कुछ लोगों को अपराध की ओर धकेलता है। हालांकि इन कारणों के आधार पर किसी भी अपराध का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। मंदिरों में चोरी केवल आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं होती; अनेक मामलों में यह संगठित अपराध, मूर्ति तस्करी और पेशेवर गिरोहों की सुनियोजित गतिविधि होती है। विशेष रूप से प्राचीन मूर्तियों और दुर्लभ धार्मिक कलाकृतियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध मांग भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है।

मंदिर में चोरी का सबसे गहरा प्रभाव श्रद्धालुओं की भावनाओं पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार की खुशहाली,बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धापूर्वक दान करता है,तो वह केवल धन नहीं देता,बल्कि अपना विश्वास भी समर्पित करता है। यदि वही विश्वास असुरक्षित महसूस करने लगे तो समाज में धार्मिक संस्थाओं के प्रति संदेह बढ़ने लगता है। कई लोग दान देने से हिचकने लगते हैं, मंदिर समितियों पर प्रश्न उठने लगते हैं और स्थानीय स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप का वातावरण बन जाता है। इस प्रकार एक चोरी केवल धन का नुकसान नहीं करती, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक एकता को भी प्रभावित करती है।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को केवल धार्मिक विषय मानना भी पर्याप्त नहीं है। यह सार्वजनिक नीति, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। जिस प्रकार बैंक, संग्रहालय,विद्यालय और सार्वजनिक संस्थानों के लिए सुरक्षा के मानक निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार मंदिरों के लिए भी न्यूनतम सुरक्षा मानक तय किए जाने चाहिए। प्रत्येक मंदिर की आय,आकार और संवेदन शीलता के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जा सकती है। बड़े मंदिरों में अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था,नियंत्रित प्रवेश,सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और डिजिटल प्रबंधन आवश्यक है,जबकि छोटे मंदिरों में स्थानीय पुलिस,ग्राम समितियों और नागरिकों के सहयोग से प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा सकता है।

आषाढ़

प्रिया देवांगन प्रियू
राजिम गरियाबंद
छत्तीसगढ़

आया है आषाढ़,साथ आ जाओ पानी।
देख रहें हैं राह, छोड़ दो अब मनमानी।।
लालच देकर रोज,कहाँ जी तुम उड़ जाते।
दिखते पानी मेघ,धरा में क्यों नहिं आते।।

गड़गड़ की आवाज,हिया में शोर मचाते।
सुनकर मानव शोर,सभी वे खुश हो जाते।।
कहीं गिराते नीर,बढ़ाते कहीं उदासी।
बेचारी ये झील,यहाँ बैठी है प्यासी।

तरसे मन उल्लास,खण्ड वर्षा ये कैसी।
कहीं धूप अरु छाँव,नहीं पहले थी ऐसी।।
आओ बारिश बूँद,रूठना अब तुम छोड़ो।
बाँटो अपना प्रेम,धरा से नाता जोड़ो।।

मानव का ये रूप,नहीं जी तुम अपनाओ।
नहीं बदलना रंग,सही पहचान दिखाओ।।
जोड़े हाथ किसान,कहे तुम नीर गिराओ।
ओ राजा आषाढ़,जरा हरियाली लाओ।।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

मैनपाट में बॉक्साइट खनन : विकास की चमक के पीछे जल-जंगल-जमीन का सवाल

जनसुनवाई में 60 आपत्तियां,ग्रामीणों ने पूछा-क्या खनिज के लिए खत्म होगी प्राकृतिक विरासत?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मैनपाट की पहचान केवल बॉक्साइट भंडार से नहीं,बल्कि उसकी पहाड़ियों,जंगलों, जलस्रोतों और प्राकृतिक सुंदरता से भी है। ऐसे क्षेत्र में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना को लेकर हुई जनसुनवाई ने एक बार फिर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच खड़े पुराने सवालों को सामने ला दिया है। रोपाखार सहित आसपास के गांवों में प्रस्तावित करीब 147 हेक्टेयर क्षेत्र की खनन परियोजना को लेकर आयोजित जनसुनवाई में 60 आपत्तियां दर्ज होना यह संकेत देता है कि स्थानीय ग्रामीणों के मन में परियोजना को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं। ग्रामीणों ने जलस्रोतों के प्रभावित होने,खेती पर असर, जैव विविधता को नुकसान और आजीविका संकट की चिंता जताई। ग्रामीणों का कहना है कि मैनपाट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खनन का असर केवल पहाड़ काटने तक सीमित नहीं रहेगा। पहाड़ों से जुड़े जलस्रोत,जंगल आधारित जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि ग्रामीणों का सवाल है कि क्या आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक संतुलन की कीमत चुकानी पड़ेगी।

सवाल सिर्फ खनन का नहीं...भरोसे का भी...

प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई केवल प्रक्रिया का हिस्सा है और सभी आपत्तियों व सुझावों का परीक्षण किया जाएगा। सीएमडीसी की ओर से भी कहा गया कि परियोजना की पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने के कारण विरोध की स्थिति बनी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि परियोजना ग्रामीणों के हित में है तो शुरुआत से ही स्थानीय लोगों के साथ संवाद और विश्वास निर्माण क्यों नहीं हो पाया? किसी भी खनन परियोजना की सफलता केवल मंजूरी और मशीनों से नहीं,बल्कि स्थानीय समुदाय के विश्वास से तय होती है।

पुराने अनुभवों से बढ़ी ग्रामीणों की चिंता : मैनपाट क्षेत्र में पहले भी बॉक्साइट खनन को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। पुराने खनन अनुभवों में भूमि, पर्यावरण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रभावित लोगों की चिंताएं सामने आई थीं। यही कारण है कि नई परियोजना को लेकर ग्रामीण केवल रोजगार और विकास के दावों को नहीं, बल्कि उसके वास्तविक प्रभावों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।

क्या विकास का मॉडल बदलेगा?

छत्तीसगढ़ में खनन परियोजनाओं को लेकर कई क्षेत्रों में यही बहस सामने आती रही है कि खनिज संपदा का उपयोग जरूरी है,लेकिन पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मैनपाट में भी अब चुनौती यही है कि सरकार और परियोजना एजेंसी यह भरोसा कैसे कायम करती है कि खनन से मिलने वाला लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचेगा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। क्योंकि मैनपाट के ग्रामीणों का विरोध केवल एक खदान का विरोध नहीं दिखता,बल्कि यह उस विकास मॉडल पर सवाल है जिसमें पहाड़,जंगल और पानी की कीमत पर प्रगति तय की जाती है। अब नजर इस बात पर होगी कि जनसुनवाई में उठी आपत्तियां सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती हैं या वास्तव में परियोजना के फैसले को प्रभावित करती हैं।

सरगुजा में रामायण शोधपीठ और कालिदास शोध संस्थान की मांग,मुख्यमंत्री को सौंपा प्रस्ताव

सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल, आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की स्थापना की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और वैश्विक पहचान दिलाने की मांग को लेकर वरिष्ठ भाजपा पार्षद एवं सरगुजा जिला पुरातत्व समिति के सदस्य आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को पत्र भेजकर सरगुजा में रामायण शोधपीठ एवं कालिदास शोध संस्थान की स्थापना का अनुरोध किया है। पत्र में आलोक दुबे ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़ी पावन भूमि रही है। यहां मौजूद अनेक पुरातात्विक अवशेष इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि संस्कृत साहित्य के महान कवि महाकवि कालिदास की अमर कृति 'मेघदूत' की प्रेरणा स्थली के रूप में भी सरगुजा का विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरगुजा में रामायण शोधपीठ और कालिदास शोध संस्थान की स्थापना होने से न केवल प्राचीन संस्कृति, साहित्य और परंपराओं का संरक्षण होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। आलोक दुबे ने अपने पत्र में तीन प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहला, इन संस्थानों के माध्यम से सरगुजा की सांस्कृतिक विरासत, रामायणकालीन संदर्भों और कालिदास साहित्य से जुड़े तथ्यों का दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। दूसरा, इससे धार्मिक एवं साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा, यह संस्थान रामायण, संस्कृत साहित्य और आदिवासी

संस्कृति पर शोध एवं अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से संबद्ध पाठ्यक्रम, शोध कार्य, कार्यशालाएं और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन से युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सरगुजा में इन संस्थानों की स्थापना छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

रामगढ़ महोत्सव में चोरी के शक में तीन महिलाओं की पिटाई

कुर्सियों से हमला करने का वीडियो वायरल,हाथ जोड़कर माफी मांगती रहीं महिलाएं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ में आयोजित दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव के समापन के बाद मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं और युवक चोरी के संदेह में तीन महिलाओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक प्लास्टिक की कुर्सियों से महिलाओं पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान एक महिला के सिर में चोट लगने से खून बहने लगा। घायल महिला सिर पर कपड़ा बांधकर रोती हुई और हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

चोरी के शक में शुरू हुआ विवाद : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामगढ़ महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ महिलाओं ने तीन महिलाओं पर चोरी का संदेह जताया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये महिलाएं भीड़ में संदिग्ध गतिविधियां कर रही थीं। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों महिलाओं को पकड़ लिया और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। वायरल वीडियो में कुछ युवक और महिलाएं तीनों महिलाओं के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।

सिर पर लगी चोट,मदद के लिए गुहार लगाती रही महिला

वीडियो में एक महिला के सिर से खून निकलता दिखाई दे रहा है। वह हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांग रही है, लेकिन भीड़ का गुस्सा काफी देर तक शांत नहीं हुआ। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बाद में बीच-बचाव कर महिलाओं को भीड़ से बाहर निकाला। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

थाने में अब तक नहीं पहुंची शिकायत

जानकारी के अनुसार घटना को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। यदि शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर सकती है।

संदेह के आधार पर मारपीट कानूनन अपराध

बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में चोरी करने वाले गिरोहों की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन केवल संदेह के आधार पर किसी के साथ मारपीट करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई का अधिकार पुलिस और प्रशासन को है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

रामगढ़ महोत्सव से लौट रहे सात किशोरों को ट्रक ने रौंदा

एक की मौत,छह गंभीर घायल,फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

रामगढ़ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर पैदल घर लौट रहे सात नाबालिग किशोर मंगलवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरडीह के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने पीछे से किशोरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि सभी किशोर सड़क पर दूर-दूर जा गिरे। दुर्घटना में एक किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। उदयपुर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

टक्कर के बाद सड़क पर मची चीख-पुकार : जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के ग्राम मंहगई श्रीनगर निवासी 15 वर्षीय विकास अगरिया पिता रिगु अगरिया अपने छह साथियों के साथ मंगलवार को रामगढ़ महोत्सव देखने आया था। उसके साथ छोटेलाल, दिनेश, देवप्रसाद, अंजय, टिलो सहित अन्य किशोर मौजूद थे। सभी की उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है। महोत्सव में कार्यक्रम देखने के बाद रात करीब 12 बजे सभी किशोर पैदल अपने गांव की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम डुमरडीह के पास अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशोर उछलकर सड़क पर जा गिरे। किसी के सिर में गंभीर चोट आई तो किसी के पैर और जबड़े में चोट लगी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

किराना दुकानदार ने दी सूचना, डायल-112 ने पहुंचाया अस्पताल : घटना के बाद घायलों की आवाज सुनकर पास के एक किराना व्यवसायी ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान 15 वर्षीय विकास अगरिया की मौत हो गई, जबकि छह अन्य किशोरों का उपचार जारी है।

बेटे के लौटने का इंतजार करता रह गया परिवार

बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए। मृतक के पिता रिगु अगरिया ने बताया कि विकास दोस्तों के साथ रामगढ़ महोत्सव देखने जाने की बात कहकर घर से निकला था। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा कार्यक्रम देखकर वापस लौट आएगा, लेकिन हादसे की खबर ने परिवार को तोड़ दिया। विकास की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों से ट्रक की तलाश

उदयपुर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से फरार ट्रक और चालक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को चिन्हित कर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई...रेत,मुरूम और गिट्टी के अवैध उत्खनन-परिवहन में सात वाहन जब्त,नियमों के तहत होगी कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अलग-अलग शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर विभाग ने अभियान चलाकर रेत,मुरूम और गिट्टी के अवैध कारोबार में संलिप्त सात वाहनों को जब्त किया है। विभाग ने सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। खनिज विभाग का कहना है कि जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसी अभियान के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर यह कार्रवाई की गई।

लुचकी घाट में जेसीबी और ट्रैक्टर पकड़े गए : जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 28 जून को अंबिकापुर तहसील के लुचकी घाट में अवैध रूप से मिट्टी-मुरूम का उत्खनन करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया। जब्त वाहनों में जेसीबी क्रमांक सीजी 15 डीएम 7967 और ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 15 एई 2137 शामिल हैं। दोनों वाहनों के मालिक इस्लाम खान बताए गए हैं। जब्त वाहनों को खनिज कलेक्टर परिसर में रखा गया है।

उदयपुर में रेत परिवहन करते टीपर जब्त : इसी तरह 29 जून को उदयपुर तहसील के ग्राम केशगवां में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते एक टीपर वाहन पकड़ा गया। वाहन क्रमांक सीजी 15 ईजे 4504 के मालिक राजा यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वाहन को उदयपुर थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

सीतापुर क्षेत्र में चार वाहनों पर कार्रवाई : सीतापुर क्षेत्र में भी खनिज विभाग ने चार वाहनों पर कार्रवाई की। इनमें रेत परिवहन में लगे दो ट्रैक्टर और गिट्टी परिवहन में उपयोग किए जा रहे दो वाहन शामिल हैं। जब्त वाहनों में सीजी 13 बीडी 5155 और सीजी 13 बीडी 5157 शामिल हैं। सभी वाहनों को सीतापुर थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है।

संशोधित नियमों के तहत लगेगा न्यूनतम 25 हजार रुपये शुल्क

खनिज विभाग ने बताया कि 22 जून 2026 से लागू संशोधित नियम 71(3) के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में न्यूनतम शमन शुल्क 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 2 हजार रुपये प्रति टन या निर्धारित न्यूनतम शुल्क, जो भी अधिक होगा, वह वसूल किया जाएगा। साथ ही संबंधित खनिज का बाजार मूल्य भी आरोपितों से वसूला जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच

दयानिधि अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, नकद वसूली और करोड़ों के भुगतान सहित कई बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पताल में कथित अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। दयानिधि अस्पताल के संचालक डॉ. संदीप त्रिपाठी के खिलाफ मिली शिकायत के बाद संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा ने सीएमएचओ सरगुजा को मामले की जांच कर छह कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए सभी बिंदुओं की सूक्ष्म जांच के लिए जांच दल गठित करने कहा है। जांच रिपोर्ट स्पष्ट अभिमत के साथ निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से नकद राशि लेने का आरोप : शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने पहुंचे कार्डधारी मरीजों से भी अस्पताल में नकद राशि ली

गई। इसके अलावा अस्पताल में इलाज और योजना के तहत किए गए भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि केवल 11 बिस्तरों वाले अस्पताल को पिछले तीन वर्षों में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसकी जांच की मांग की गई है।

कर्मचारियों की मिलीभगत से राशि जमा करने का आरोप : शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मरीजों से ली गई राशि कर्मचारियों की मिलीभगत से सीधे अस्पताल के खाते में जमा कराई जाती थी। इसके अलावा डॉ. संदीप त्रिपाठी पर शासकीय अवकाश के दौरान निजी अस्पताल में उपचार करने और अनियमितताओं में संलिप्त रहने के आरोप भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन आरोपों की सत्यता जानने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान अस्पताल के रिकॉर्ड, मरीजों से संबंधित दस्तावेज और भुगतान संबंधी जानकारी की जांच की जाएगी।

छह दिन में देनी होगी रिपोर्ट : संभागीय संयुक्त संचालक ने 30 जून को जारी पत्र में सीएमएचओ को जांच पूरी कर छह कार्यदिवस के भीतर प्रतिवेदन सौंपने कहा है। जांच पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय नवा रायपुर, सरगुजा संभाग के आयुक्त और सरगुजा कलेक्टर को भी भेजी गई है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई होगी।

सर्पदंश से ग्रामीण की मौत : खेत में धान उठाने गए किसान को सांप ने डसा,इलाज के दौरान अंबिकापुर अस्पताल में तोड़ा दम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले में सर्पदंश से एक ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीण खेत में गर्मी में लगाए गए धान को उठाने गया था, इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी जान नहीं बच सकी। जानकारी के अनुसार त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गोवर्धनपुर निवासी लालमन यादव पिता केशर यादव (56) 29 जून की शाम करीब 5 बजे अपने खेत में धान उठाने के लिए गया था। इसी दौरान खेत में मौजूद जाड़ा सांप ने उसे डस लिया।

पहले डिण्डो स्वास्थ्य केंद्र में कराया इलाज

सर्पदंश के बाद परिजन तत्काल लालमन यादव को डिण्डो स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां आवश्यक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर रिश्तेदार के घर रुक गए। अगले दिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन दोबारा डिण्डो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें वाड्रफनगर रेफर किया गया।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई मौत

वाड्रफनगर से परिजन लालमन यादव को मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

ट्रक की ठोकर से दंपति घायल पति की इलाज के दौरान मौत

महान पुल के पास हुआ हादसा,पत्नी का अस्पताल में चल रहा उपचार,पुलिस ने दर्ज किया मामला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी का उपचार जारी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसवारपारा निवासी शंकर लकड़ा पिता स्व. परषोत्तम लकड़ा (42) मंगलवार सुबह अपनी पत्नी बालपति के साथ मोटरसाइकिल से खड़गवां जाने के लिए निकले थे।

महान पुल के पास ट्रक ने मारी टक्कर

बताया जा रहा है कि दोनों महान पुल के पास पहुंचे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दंपति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना दी और दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर पहुंचाया गया।

CMYK

जनदर्शन में मंत्री राजेश अग्रवाल ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं,त्वरित समाधान के दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड लखनपुर की ग्राम पंचायत परसोंडी पहुंचकर ग्रामीणजनों से आत्मीय भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने पेयजल, सड़क,विद्युत, राजस्व,सामाजिक सुरक्षा,शिक्षा,स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े विषय मंत्री श्री अग्रवाल के समक्ष रखे। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है, जहां आम नागरिक अपनी बात सीधे रख सकता है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास के संकल्प को साकार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

शाला प्रवेश उत्सव में मंच व्यवस्था को लेकर नाराज हुईं सामरी विधायक, उठा सवाल-बच्चों का उत्सव या वीआईपी प्रोटोकॉल का मंच?

बैठक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार,कुछ देर के लिए बिगड़ा कार्यक्रम का माहौल

-संवाददाता-
राजपुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उस समय असहज स्थिति निर्मित हो गई, जब मंच की बैठक व्यवस्था को लेकर सामरी विधायक उदधेश्वरी पैकरा नाराज हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,मंच के सामने लगाए गए नेमप्लेट और बैठने की व्यवस्था को लेकर विधायक ने आपत्ति जताई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मंच पर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारियों के बैठने के क्रम को लेकर संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद कुछ समय के लिए कार्यक्रम का माहौल प्रभावित हुआ। हालांकि सवाल यह है कि जिस कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत करना, उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह और विश्वास जगाना था, वहां चर्चा का केंद्र बच्चों की खुशी के बजाय मंच की कुर्सियां और प्रोटोकॉल क्यों बन गया?

बच्चों के कार्यक्रम में भी हावी हो रहा वीआईपी कल्चर? शाला प्रवेश उत्सव जैसे आयोजनों में आमतौर पर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में मंच पर कौन कहां बैठेगा,किसका नेमप्लेट कहां लगेगा–इन बातों को लेकर विवाद होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ऐसे अवसरों पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चे और अभिभावक ऐसे कार्यक्रमों से सकारात्मक संदेश की उम्मीद लेकर आते हैं।

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

कुछ अभिभावकों ने कहा कि नेताओं को बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों में संयम और सरलता का परिचय देना चाहिए। मंच की व्यवस्था को लेकर विवाद का असर कार्यक्रम के माहौल पर पड़ता है और इसका संदेश बच्चों तक भी जाता है। लोगों का सवाल है कि क्या शिक्षा से जुड़े आयोजनों में भी वीआईपी संस्कृति को प्राथमिकता मिलेगी या फिर ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों का उत्साह ही सबसे ऊपर रहेगा? समाचार लिखे जाने तक मामले में विधायक उदधेश्वरी पैकरा और शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

प्रतापपुर पुलिस ने 6 लाख की चोरी गई कार बरामद कर आरोपी को दबोचा

तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना से मिली सफलता,आरोपी से चोरी की हुंडई आई20 कार व अन्य सामग्री जब्त

-संवाददाता-
सूरजपुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

थाना प्रतापपुर पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए चोरी गई हुंडई आई 20 कार बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की कार के साथ प्रकरण से संबंधित अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं, मामले में आगे की विवेचना जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मानी निवासी समीउल्लाह ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून 2026 की रात करीब 9 बजे वह प्रतापपुर बाजार स्थित अपने मोटर साइकिल गैराज को बंद कर रहे थे,इस दौरान उन्होंने अपनी हुंडई आई20 कार (क्रमांक CG09J-8413) की चाबी तलाश की,लेकिन चाबी नहीं मिलने पर कार को गैराज के बाहर खड़ा छोड़कर घर चले गए। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे जब वह दुकान पहुंचे तो दुकान के सामने खड़ी कार गायब थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार चोरी कर ली गई थी। चोरी गई कार की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई, प्रार्थी की शिकायत पर थाना प्रतापपुर में अपराध क्रमांक 182/2026 के तहत धारा 303(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी गई कार की बरामदगी के निर्देश दिए, इसके बाद थाना प्रतापपुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जांच के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महताब अंसारी (30 वर्ष),पिता जलालुद्दीन, निवासी गोपालपुर, थाना राजपुर,जिला बलरामपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की,पूछताछ में आरोपी से मिली जानकारी (मेमोरेंडम) के आधार पर चोरी गई हुंडई आई20 कार तथा प्रकरण से संबंधित अन्य सामग्री बरामद कर ली गई,पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को 1 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की,थाना प्रतापपुर पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है तथा यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी अन्य वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं, पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से वाहन चोरी के मामले का शीघ्र खुलासा हुआ है, जिससे क्षेत्र के वाहन मालिकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है।

मौत का घाट' कहलाने वाले पेण्डारी को मिलेगा सुरक्षित स्वरूप

डीजीपीएस सर्वे शुरू, सर्वे रिपोर्ट के बाद तय होगा सड़क चौड़ीकरण...घाट कटिंग या पुल निर्माण का विकल्प

-संवाददाता-
प्रतापपुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

लगातार सड़क हादसों के कारण 'मौत का घाट' के नाम से पहचाने जाने वाले प्रतापपुर क्षेत्र के पेण्डारी घाट को अब सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने लोक निर्माण विभाग के वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में इस महत्वपूर्ण परियोजना को शामिल किया है। इसके तहत अंबिकापुर-धनवार-वाराणसी राज्य मार्ग (एसएच-2ए) स्थित पेण्डारी घाट में डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग सूरजपुर संभाग की निगरानी में तकनीकी विशेषज्ञ पूरे घाट क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं। विभाग के उपअभियंता सुधीर बड़ा की मौजूदगी में सर्वे टीम घाट की भौगोलिक स्थिति, सड़क की संरचना और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर रही है।

सर्वे के बाद तय होगा निर्माण का स्वरूप : डीजीपीएस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि पेण्डारी घाट में किस तरह का निर्माण जरूरी है। इसमें घाट कटिंग, सड़क चौड़ीकरण, रिटेनिंग वॉल निर्माण या व्हायाडक्ट (ऊंचा पुल) जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

खतरनाक मोड़ और ढलान बनते हैं हादसों का कारण : पेण्डारी घाट लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं के लिए बदनाम रहा है। यहां तीखे मोड़, अधिक ढलान और सड़क किनारे गहरी खाई के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में फिसलन और कम दृश्यता के कारण हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस घाट में कई दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग रही है कि घाट को सुरक्षित बनाया जाए।

विधायक की पहल से आगे बढ़ी प्रक्रिया : प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि पेण्डारी घाट की समस्या को उन्होंने लगातार विधानसभा में उठाया और सुरक्षित निर्माण की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वे की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

लोगों को सुरक्षित आवागमन की उम्मीद : क्षेत्रवासियों का कहना है कि पेण्डारी घाट के सुरक्षित निर्माण से प्रतापपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर के बीच आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। लोगों को उम्मीद है कि वर्षों से हादसों की पहचान बन चुका पेण्डारी घाट जल्द ही सुरक्षित मार्ग के रूप में नई पहचान हासिल करेगा।

राजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : पशु तस्करी मामले में दो और फरार आरोपी गिरफ्तार,अब तक 4 आरोपी जेल भेजे गए

12 नग भैंस,पिकअप वाहन और ब्रेजा कार जब्त

-संवाददाता-
राजपुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना पुलिस ने पशु तस्करी के चर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन,ब्रेजा कार सहित 12 नग भैंसों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में पशु तस्करी एवं अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना राजपुर पुलिस को पशु तस्करी प्रकरण में सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार दिनांक 11.06.2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप वाहन क्रमांक P-65 QT-1375 में भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर वध के लिए उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम गोपालपुर के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका। जांच के दौरान वाहन में 12 नग भैंस अमानवीय एवं क्रूरतापूर्ण तरीके से परिवहन करते पाए गए। मौके से पुलिस ने वाहन चालक अशोक गिरी को गिरफ्तार किया था, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए थे।

प्रकरण में एक पिकअप वाहन, ब्रेजा कार एवं 12 नग भैंसों को जब्त कर ग्राम बासेन स्थित गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर फरार आरोपी सलमान उर्फ सहजाद आलम को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में पुलिस ने फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों अभिमन्यु गिरी पिता दिलीप गिरी (23 वर्ष) एवं निखिल गिरी पिता जोगेंद्र गिरी (26 वर्ष) दोनों निवासी थाना चकिया, जिला चंदौली (उत्तर प्रदेश) को 01.07.2026 को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जेएनएफसी न्यायालय राजपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें 03.07.2026 तक न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रामानुजगंज भेज दिया गया है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2026 में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में एएसआई अशोक तिर्की, प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रतीक नेताम, दयाराम वट्टी, आरक्षक रुपेश गुप्ता एवं सैनिक शैलेंद्र गुप्ता की

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने जनजातीय प्रतिनिधियों से किया संवाद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस अम्बिकापुर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो,लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपमा सिंह,जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री रामकिसुन सिंह,पूर्व सरगुजा सांसद श्री कमलभान सिंह,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से श्री पुरूनेन्दु कांत,श्री पी.के.दास,सोनल राज, एच.आर.मीना, जे.पी.सिंह तथा कुलेश्वर साहू, जनजातीय समाज के विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधि,पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉ.लकड़ा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार, कर्तृत्वों एवं कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनके सामाजिक,शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु निरन्तर कार्यरत है। उपस्थित समाज प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों से जनजातीय समुदाय से संबंधित समस्याओं,चुनौतियों एवं मांगो को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। इस दौरान समाज प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र एवं समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। इस दौरान सड़क निर्माण,क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत, जनजातीय भूमि संरक्षण,बॉक्साईट खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए उचित मुआवजा, जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याएं, कोरवा एवं पंडो अनुसूचित जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करने,हाथी विचरण क्षेत्रों की समस्या तथा सरना स्थलों के संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

कार्यालय अधिक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) ,मण्डल बिलासपुर (छ0ग0)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

नि.आ.सू. दिनांक 25/06/2026 तथा **Online Bid Submission** की अंतिम तिथि 07/07/2026
Physical Submission Last Date 13/07/2026
ऑनलाईन निविदा तृतीय आमंत्रण

क्र.	नि.आ.सू. क्रमांक	ऑनलाईन टेण्डर नंबर	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1	28	194196	Supplying & instalation of D. G. Set for 1 No. Court Room at Navagarh, Distt- Janjgir Champa (C.G.)	11.96

नि.आ.सू. दिनांक 25/06/2026 तथा **Online Bid Submission** की अंतिम तिथि 07/07/2026
Physical Submission Last Date 17/07/2026
ऑनलाईन निविदा द्वितीय आमंत्रण

2	29	194215	SITC of 200 KVA Diesel Generating Set for 03 No. Court Room at |Akaltara, Block Akaltara, Distt. Janjgir Champa (C.G.)	19.81
3	30	194222	Providing Line Shifting of poles from Ludeg to Tapkara Road, Distt.- |Jashpur (C.G.)	56.00
4	31	194234	Providing Electrification work in Residential building in block |Gaurela and Marwahi Distt. G.P.M. (C.G.)	13.10

नि.आ.सू. दिनांक 25/06/2026 तथा **Online Bid Submission** की अंतिम तिथि 13/07/2026
Physical Submission Last Date 17/07/2026
ऑनलाईन निविदा प्रथम आमंत्रण

5	32	192242	SITC of LED Street lights at proposed NH 49 (BTI Chauk to ROB | Khoksa Chauk length 1400 Metre) at Janjgir, District -Janjgir-Champa (C.G.)	55.24
6	33	194247	Providing High Masts and Street Light for construction of widening and strenthing Indira Chowk to Jashpur road length 2.00 | KM, Indira Chowk to Ambikapur road length 1.50 KM & Indira | Chowk to Raigarh road length 3.80KM total length 7.30 KM at | Pathalgaon Block-Pathalgaon, Distt.-Jashpur (C.G.)	169.95
7	34	194301	Providing Street Light to four lane road at Gandhi Chowk to Railway Station, Ambikapur (C.G.) (Length 5.54KM)	155.00
8	35	194304	Providing, Street Light to Larang Sai Chowk to Ramanujganj |road, Ambikapur Distt. Surguja (C.G.) (Length 6.38KM)	190.00

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि., (वि./ यां.) मण्डल
बिलासपुर (छ.ग.)

जी0नं0 -262701779/3

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक नरेश कुमार आ0 स्व0 जीवन राम अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी राम मंदिर रोड़, ब्रम्ह वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला राम मंदिर मैदान, नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर - 11 क स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 3196/4813/119 रकबा 0.03$^{1/2}$ एकड़ भूमि में से रकबा 0.01$^{3/4}$ एकड़ भूमि को अपने पुत्र अनावेदक मुकेश अग्रवाल आ0 नरेश कुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी राम मंदिर रोड़, ब्रम्ह वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर के पक्ष में दान करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नौगई हत्याकांड : क्या पुलिस की चूक से हुई तीन लोगों की दर्दनाक मौत?

नौगई तिहरे हत्याकांडः क्या पुलिस की एकपक्षीय सतर्कता ने ले ली तीन लोगों की जान?

संभावित वारदात की जानकारी थी...फिर भी नहीं रुका नौगई हत्याकांड...पुलिस की भूमिका पर बड़ा सवाल...

- जब वारदात की आशंका थी तो थाना प्रभारी मुख्यालय से बाहर क्यों थे? नौगई हत्याकांड में उठे गंभीर सवाल
- नौगई तिहरे हत्याकांड : निगरानी एक पक्ष पर,हमला दूसरे पक्ष से,पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल...
- क्या नौगई हत्याकांड टाला जा सकता था? पुलिस की रणनीति और निर्णय अब जांच के घेरे में...
- नौगई तिहरे हत्याकांडः संभावित खतरे की जानकारी के बावजूद क्यों नहीं रोकी जा सकी वारदात?
- नौगई तिहरे हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल,क्या एकपक्षीय कार्रवाई ने बिगाड़ दिए हालात?
- सीबीआई जांच से बढ़ीं उम्मीदें,घटना से पहले पुलिस की तैयारी,थाना प्रभारी की अनुपस्थिति,दोनों पक्षों की निगरानी और प्रारंभिक कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की उठ रही मांग...

क्या पुलिस की निगरानी एकपक्षीय थी?

घटना के बाद कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि पुलिस की सक्रियता मुख्य रूप से पीड़ित पक्ष के इर्द-गिर्द दिखाई दी, आरोप है कि पुलिस उनके आवागमन,वाहनों और गतिविधियों पर अधिक नजर रख रही थी,जबकि बाद में हत्या के आरोपी बने दूसरे पक्ष की गतिविधियों पर उतनी सतर्कता नहीं दिखाई गई, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन यही वे प्रश्न हैं जिन्हें अब निष्पक्ष जांच में स्पष्ट किए जाने की मांग की जा रही है।

प्रारंभिक पुलिस बयान भी विवादों में रहे...

घटना के शुरुआती चरण में पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए कुछ सार्वजनिक बयान भी चर्चा का विषय बने, शुरुआती जानकारी में घटना की प्रकृति को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं,बाद में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी,हत्या और हिंसा के गंभीर आरोपों के आधार पर मामला दर्ज हुआ, पीड़ित परिवार और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि प्रारंभिक बयानों और बाद में सामने आए तथ्यों के बीच अंतर की भी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शुरुआती जानकारी किन तथ्यों के आधार पर साझा की गई थी।

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16-17 जून की दरमियानी रात हुए तिहरे हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का रास्ता साफ हो चुका है, ऐसे में केवल हत्या की घटना ही नहीं, बल्कि घटना से पहले और बाद में पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर सवाल फिर से चर्चा में आ गए हैं, पीड़ित परिवार, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अब सीबीआई को यह भी जांचना चाहिए कि क्या पुलिस की रणनीति, निगरानी और निर्णयों में किसी स्तर पर ऐसी चूक हुई, जिसने इस जघन्य वारदात को होने दिया। घटना के बाद से लगातार यह बात सामने आती रही कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की जानकारी पुलिस को पहले से थी, पुलिस स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव था और किसी अप्रिय घटना की आशंका भी थी, यदि ऐसा था, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या पुलिस ने दोनों पक्षों पर समान रूप से निगरानी रखी थी, या उसकी सक्रियता केवल एक पक्ष तक सीमित रही?

सुबह विवाद दर्ज...दिनभर समझौते की कोशिश...रात में हो गया तिहरा हत्याकांड

उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार,वारदात वाले दिन दोनों पक्षों के बीच विवाद की जानकारी पुलिस तक पहुंची थी,थाने में शिकायत दर्ज हुई,समझौते के प्रयास भी किए गए और पुलिस दिनभर मामले को शांत कराने में लगी रही,इसी दौरान पुलिस की गतिविधियां मुख्य रूप से उस पक्ष के इर्द-गिर्द दिखाई दीं,जो बाद में पीड़ित पक्ष बना, स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि पुलिस को संभावित बड़ी वारदात की आशंका थी, तो आरोपी पक्ष की गतिविधियों पर भी समान रूप से निगरानी क्यों नहीं रखी गई? क्या पुलिस ने दोनों पक्षों की जोखिम का समान आकलन किया था? या फिर एक पक्ष को ही संभावित समस्या मान लिया गया?

सबसे बड़ा सवाल—संभावित बड़ी वारदात के बीच थाना प्रभारी मुख्यालय से बाहर क्यों थे?- पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित प्रश्न थाना प्रभारी सोनहत की भूमिका को लेकर है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस को गंभीर टकराव की आशंका थी, तो उस समय थाना प्रभारी का अपने थाना क्षेत्र से बाहर होना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है, बताया गया कि थाना प्रभारी किसी अन्य थाने के चोरी के मामले के संबंध में बाहर गए थे, वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा रही कि साइबर सेल से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी अलग-अलग जानकारियां सामने आईं, ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि स्थिति इतनी संवेदनशील थी तो क्या थाना प्रभारी का मुख्यालय छोड़ना आवश्यक था? क्या उपलब्ध परिस्थितियों में उनका थाना क्षेत्र में रहना कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होता?

क्या किसी पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय होगी?

घटना के बाद एक सब-इंस्पेक्टर को हटाए जाने की जानकारी सामने आई थी,लेकिन अब भी यह प्रश्न बना हुआ है कि यदि घटना संभावित होने की जानकारी पहले से थी,तो क्या केवल एक अधिकारी की भूमिका की समीक्षा पर्याप्त है? पीड़ित परिवार लगातार मांग करता रहा है कि थाना प्रभारी, उस समय के प्रभारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी विभागीय और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए,उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कर्तव्य में शिथिलता पाई जाती है तो उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

अब सीबीआई जांच से बढ़ीं अपेक्षाएं

राज्य शासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी केवल हत्या की घटना ही नहीं,बल्कि उससे पहले के पूरे घटनाक्रम, पुलिस की तैयारियों, निगरानी व्यवस्था,निर्णय प्रक्रिया और घटना के बाद की कार्रवाई का भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण करेगी,यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी स्तर पर पुलिस की ओर से लापरवाही हुई, किसी सूचना पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में चूक हुई,तो उन तथ्यों पर भी कानून के अनुरूप निर्णय लिया जा सकेगा।

उठ रहे प्रमुख सवाल...

- पुलिस को सुबह से तनाव की जानकारी थी, फिर भी हत्या क्यों नहीं रोकी जा सकी?
- क्या निगरानी केवल एक पक्ष तक सीमित थी?
- आरोपी पक्ष की गतिविधियों पर बराबर नजर क्यों नहीं रखी गई?
- थाना प्रभारी संभावित बड़ी वारदात के बीच दूसरे थाना क्षेत्र में क्यों थे?
- क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने इस निर्णय की समीक्षा की?
- क्या शुरुआती पुलिस बयान घटना की गंभीरता के अनुरूप थे?
- किसी पुलिस अधिकारी की जवाबदेही अब तक तय क्यों नहीं हुई?
- क्या सीबीआई पुलिस की भूमिका और संभावित लापरवाही की भी जांच करेगी?

गरीबों का हक किसने छीना? प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल!

कोरिया जिले की कई पंचायतों में अपात्रों को आवास...पात्र गरीब अब भी बेघर

एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाभ, अविवाहित युवाओं तक के नाम सूची में होने के आरोप, सूची से नाम न काटने के बदले वसूली की चर्चाएं...

विशेष पड़ताल : बैकुंठपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों से उठे सवाल

बैकुंठपुर/कोरिया,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के घर के न रहे, इसी उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बनी,लेकिन कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत की कई ग्राम पंचायतों में इस योजना की दूसरी चरण की हितग्राही सूची ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार सूची में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करते,जबकि वास्तव में गरीब और कच्चे मकानों में रहने वाले अनेक परिवार सूची से बाहर हैं,आरोप केवल अपात्रों को लाभ दिलाने तक सीमित नहीं हैं,बल्कि सर्वे प्रक्रिया, ग्राम सभा, नाम जोड़ने और नाम न काटने के नाम पर कथित अवैध वसूली तक की चर्चाएं गांव-गांव में हो रही हैं,यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो यह केवल पंचायत स्तर की अनियमितता नहीं,बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकती है।

प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना पर आखिर किसकी नजर?- प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, योजना में निर्माण की राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में भेजी जाती है तथा मजदूरी का भुगतान मनरेगा के माध्यम से किया जाता है ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम हो, लेकिन बैकुंठपुर जनपद की कई पंचायतों से सामने आ रही शिकायतें इस व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्न उठा रही हैं, ग्रामीणों का कहना है कि योजना की भावना के विपरीत प्रभावशाली और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है।

पात्र कौन,अपात्र कौन...नियम कुछ और, सूची कुछ और?- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे परिवार सामान्यतः पात्र नहीं माने जाते जिनके पास–पहले से पक्का मकान हो, चार पहिया वाहन अथवा पर्याप्त आर्थिक संसाधन हों, निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि हो,सरकारी नौकरी या नियमित उच्च आय हो,आयकरदाता हों, संयुक्त परिवार में अलग पात्रता न बनती हो,इसी प्रकार एक ही राशन कार्ड में शामिल संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग आवास देने का भी प्रावधान सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, ग्रामीणों का आरोप है कि इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई।

पंचायतों में क्यों मची है सूची को लेकर हलचल?- विशेष ग्राम सभाओं में जैसे-जैसे हितग्राहियों की सूची सामने आ रही है, वैसे-वैसे विरोध भी बढ़ रहा है,ग्रामीणों का कहना है कि जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उनके नाम सूची में हैं,कई परिवारों के पास ट्रैक्टर और चार पहिया वाहन हैं,कुछ लोगों के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि है, कई प्रभावशाली परिवारों को लाभार्थी बनाया गया है, वास्तविक गरीबों के नाम सूची से गायब हैं, यदि यह सही है तो यह केवल पात्रता का मामला नहीं बल्कि गरीबों के अधिकारों से जुड़ा विषय है।

क्या सर्वे में ही हो गया पूरा खेल?- पूरे मामले की जड़ सर्वे प्रक्रिया को माना जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र परिवारों का ऑनलाइन सर्वे पंचायत सचिव,रोजगार सहायक तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा किया गया,ग्रामीणों का आरोप है कि सर्वे निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया,कई लोगों का कहना है कि गरीब परिवारों के घर तक टीम नहीं पहुंची, जिनका सर्वे होना चाहिए था,उनका नाम दर्ज नहीं किया गया,प्रभावशाली लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े गए,कथित रूप से पैसे लेकर पात्रता तैयार की गई, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

नाम न काटने के बदले वसूली?- ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गंभीर चर्चा इस बात को लेकर है कि सूची सार्वजनिक होने के बाद जिन लोगों के नाम पात्रता पर सवालों के घेरे में आए, उनसे कथित रूप से यह कहा गया कि यदि नाम कटने से बचाना है तो पैसे देने होंगे, यदि इस प्रकार की शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीबों के अधिकारों का आर्थिक शोषण भी माना जाएगा।

एक ही परिवार के कई लोगों को आवास?- ग्रामीणों का आरोप है कि कई पंचायतों में एक ही राशन कार्ड वाले परिवार के कई सदस्यों के नाम सूची में हैं,संयुक्त परिवार के सदस्यों को अलग-अलग लाभार्थी बनाया गया, अविवाहित युवाओं तक के नाम सूची में दर्ज हैं, यदि ऐसा हुआ है तो पात्रता निर्धारण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

पहले चरण में भी उठे थे सवाल- ग्रामीण बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में भी कई ऐसे लोगों को लाभ मिला था जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, अब दूसरे चरण में भी उसी प्रकार की शिकायतें सामने आने से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

जांच हुई तो कई पंचायतों में खुल सकते हैं बड़े राज

- कितने लाभार्थियों के पास पहले से पक्का मकान है?
- कितनों के पास चार पहिया वाहन हैं?
- कितनों के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है?
- कितनों का राशन कार्ड संयुक्त है?
- कितने लाभार्थी वास्तव में अलग परिवार हैं?
- सर्वे किसने किया?
- ग्राम सभा में कितनी आपत्तियां दर्ज हुईं?
- कितनी आपत्तियों का निराकरण हुआ?

'घटती-घटना' के 10 बड़े सवाल

- क्या सूची जारी होने से पहले प्रत्येक हितग्राही का भौतिक सत्यापन हुआ?
- जिनके पास पहले से पक्का मकान है, वे सूची में कैसे पहुंचे?
- क्या एक ही राशन कार्ड वाले कई लोगों को लाभ दिया जा रहा है?
- क्या अविवाहित युवाओं को भी हितग्राही बनाया गया?
- सर्वे का आधार क्या था?
- ग्राम सभा में उठी आपत्तियों का क्या हुआ?
- पात्र गरीबों के नाम क्यों छूटे?
- क्या सूची में नाम बनाए रखने के लिए अवैध वसूली हुई?
- यदि शिकायतें सही हैं तो जिम्मेदार कौन?
- क्या जिला प्रशासन स्वतंत्र जांच कराएगा?

जिम्मेदारी आखिर किसकी?- यदि पंचायत स्तर पर अनियमितता हुई है तो पंचायत सचिव,रोजगार सहायक और आवास मित्र की भूमिका की जांच आवश्यक होगी,यदि जनपद स्तर पर बिना परीक्षण के सूची आगे भेजी गई तो जनपद पंचायत की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए,यदि जिला स्तर पर भी बिना सत्यापन सूची स्वीकृत हुई है तो प्रशासनिक निगरानी पर भी प्रश्न उठेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख पात्रता बिंदु...

- पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- पात्रता का निर्धारण शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार।
- निर्धारित आर्थिक एवं सामाजिक मानकों का पालन आवश्यक।
- सर्वे एवं ग्राम सभा के सत्यापन के बाद अंतिम सूची।
- गलत जानकारी देकर लाभ लेना नियम विरुद्ध है।

प्रशासन से मांग...

- प्रत्येक ग्राम पंचायत की सूची का पुनः भौतिक सत्यापन।
- अपात्रों के नाम तत्काल हटाए जाएं।
- छूटे पात्र परिवारों को शामिल किया जाए।
- सर्वे प्रक्रिया की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई।
- कथित अवैध वसूली की स्वतंत्र जांच।
- पूरी सूची सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन का पक्ष- *इस संबंध में जनपद पंचायत बैकुंठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,संबंधित पंचायत सचिवों एवं जिला प्रशासन का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका, उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।*

नौगई हत्याकांड के 15 वें दिन जागा कोरिया का क्षत्रिय समाज,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सीबीआई से निष्पक्ष जांच,फास्ट ट्रैक कोर्ट,आर्थिक सहायता और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग...

जिले में सामाजिक स्तर पर पहली संगठित पहल, अन्य समाजों की ओर से अब तक नहीं आया कोई सामूहिक ज्ञापन

रवि सिंह

कोरिया,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16-17 जून3 की दरमियानी रात हुए बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड को 15 दिन पूरे होने के बाद आखिरकार जिले का क्षत्रिय समाज भी संगठित रूप से सामने आया। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को न्याय तथा विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। गौरतलब है कि नौगई हत्याकांड ने न केवल कोरिया जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देशभर के लोगों को झकझोर दिया था, एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या तथा दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना के बाद विभिन्न राज्यों में क्षत्रिय समाज ने विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपे थे, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक नेतृत्वकर्ता भी मृतकों के परिजनों से मिलने कोरिया पहुंचे और न्याय की मांग को समर्थन दिया, हालांकि जिले में सामाजिक संगठनों की ओर से सामूहिक स्तर पर यह पहला ज्ञापन माना जा रहा है, अब तक

किसी अन्य समाज या सामाजिक संगठन की ओर से इस प्रकार का संगठित ज्ञापन प्रशासन को नहीं सौंपा गया था।

ज्ञापन में रखी गई कई महत्वपूर्ण मांगें-

क्षत्रिय समाज ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि नौगई हत्याकांड की जांच पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से कराई जाए तथा सभी आरोपियों की पहचान और भूमिका का समुचित परीक्षण किया जाए, समाज ने कहा कि यदि घटना में अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए, समाज ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराते हुए दोषियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने की मांग भी की।

आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा की मांग...

ज्ञापन में मृतकों के आश्रित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने,उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने तथा गंभीर रूप से घायल लोगों के संपूर्ण उपचार का खर्च शासन द्वारा वहन किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई,समाज का कहना है कि घटना में परिवार ने अपने कमाऊ सदस्यों को खो दिया है, ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ आर्थिक पुनर्वास भी उतना ही आवश्यक है।

गवाहों और साक्ष्यों की सुरक्षा की मांग...

क्षत्रिय समाज ने प्रशासन से यह भी मांग की कि मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या हस्तक्षेप जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।

उप पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर उठाए सवाल- ज्ञापन में समाज ने उप पुलिस अधीक्षक कोरिया की प्रारंभिक कार्यप्रणाली और सार्वजनिक बयानों पर भी आपत्ति जताई, समाज का आरोप है कि शुरुआती बयानों से घटना को लेकर भ्रम की स्थिति बनी और मामले की गंभीरता पूरी तरह सामने नहीं आ सकी, इसी आधार पर समाज ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा उनका स्थानांतरण किए जाने की मांग प्रशासन से की है।

प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी की भूमिका की जांच की मांग- ज्ञापन में एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी का भी उल्लेख किया गया है, समाज ने उनके संबंध में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक उनका सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण किए जाने की मांग की है,ताकि विवेचना किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रह सके।

अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की मांग...

क्षत्रिय समाज ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि यदि मामले के आरोपियों द्वारा किसी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सीबीआई जांच के बाद बढ़ी नई उम्मीद

ज्ञापन ऐसे समय सौंपा गया है जब राज्य शासन नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई को अधिकार क्षेत्र देने संबंधी अधिसूचना जारी कर चुका है,समाज के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि अब स्वतंत्र जांच एजेंसी पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों के साथ-साथ यदि किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी, समाज ने प्रशासन से आग्रह किया कि न्याय केवल समय पर ही नहीं बल्कि निष्पक्ष भी होना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

38 वर्ष की सेवा के बाद एसआई अश्वनी पाण्डेय और 28 वर्ष की सेवा के बाद आरक्षक रामप्रसाद सेवानिवृत्त

सूरजपुर पुलिस ने भावभीनी विदाई देकर किया सम्मानित,डीआईजी-एसएसपी ने कहा-कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी की मिसाल हैं दोनों अधिकारी

-संवाददाता-

सूरजपुर,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को पुलिस विभाग में दीर्घकालीन एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारी के सम्मान में गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया, समारोह में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रशांत कुमार ठाकुर ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षक (एसआई) अश्वनी पाण्डेय एवं आरक्षक रामप्रसाद को शॉल,श्रीफल और स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्हें पेंशन स्वीकृति आदेश भी सौंपे गए।

अपने संबोधन में डीआईजी-एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि एसआई अश्वनी पाण्डेय ने 38 वर्ष 10 माह तथा आरक्षक रामप्रसाद ने 28 वर्ष 7 माह तक पुलिस विभाग में निष्ठा,अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी हैं,उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का माध्यम है,अपने पूरे सेवाकाल में दोनों अधिकारियों ने ईमानदारी,कर्तव्यपरायणता और अनुशासित कार्यशैली का परिचय दिया,जो आने वाली पीढ़ी के पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा,उन्होंने दोनों सेवानिवृत्त कर्मियों के स्वस्थ, सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विभाग उनके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद रखेगा,विदाई समारोह में सेवानिवृत्त एसआई अश्वनी पाण्डेय एवं आरक्षक रामप्रसाद ने अपने लंबे सेवाकाल के अनुभव साझा किए, उन्होंने विभाग द्वारा दिए गए सम्मान और सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों तथा सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही उन्होंने युवा पुलिसकर्मियों से अपने दायित्वों का ईमानदारी,संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी दोनों सेवानिवृत्त साथियों के साथ बिताए गए कार्यकाल की यादें साझा कीं और उनके उत्तम स्वास्थ्य,दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना की, इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन,सीएसपी बेनार्ड कुजूर सहित जिला पुलिस कार्यालय तथा विभिन्न थाना-चौकियों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह भावनात्मक माहौल के बीच संपन्न हुआ, जहां सभी ने दोनों अधिकारियों की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी।

कांग्रेस नेता के.डोमरू रेड्डी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत,आबकारी विभाग की जांच के बाद भी उठे कई सवाल

शराब की गुणवत्ता खराब,पानी मिलाकर बिक्री की उपभोक्ताओं से मिल रही शिकायतों का दावा... उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

चिरमिरी,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

चिरमिरी शहर में कथित रूप से मिलावटी शराब की बिक्री को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता,जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने मोर्चा खोल दिया है,उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि शहर की अधिकांश देशी एवं अंग्रेजी शराब दुकानों में लंबे समय से कथित रूप से मिलावटी शराब की बिक्री हो रही है, शिकायत के बाद आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न शराब दुकानों पर जांच की,जिससे शहर में पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई। रेड्डी का कहना है कि उन्हें लगातार शराब उपभोक्ताओं से शिकायतें मिल रही थीं कि शराब की गुणवत्ता खराब है तथा उसमें कथित रूप से मिलावट की जा रही है,इन शिकायतों के आधार पर उन्होंने स्वयं कई दुकानों के आसपास जाकर जानकारी जुटाई और उसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद हरकत में आया आबकारी विभाग

शिकायत दर्ज होने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने चिरमिरी के विभिन्न देशी एवं अंग्रेजी शराब दुकानों का निरीक्षण किया,विभागीय टीम ने दुकानों और भंडारण स्थलों की जांच भी की,लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी स्थान पर मिलावटी शराब मिलने की पुष्टि नहीं हुई,हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच की सूचना पहले ही संबंधित लोगों तक पहुंच जाने के कारण संभावित सबूत हटाए जा सकते हैं, जिससे जांच का उद्देश्य प्रभावित हो जाता है।

उपभोक्ताओं ने टीम के सामने भी गुणवत्ता पर उठाए सवाल

के. डोमरू रेड्डी का दावा है कि जांच के दौरान डोमनहिल, गोदरीपारा एवं छोटा बाजार स्थित शराब दुकानों में मौजूद कुछ ग्राहकों ने आबकारी टीम के सामने ही शराब की गुणवत्ता पर सवाल उठाए,उनके अनुसार कुछ उपभोक्ताओं ने कथित रूप से कहा कि सामान्य दिनों में शराब पतली या पानी मिली हुई प्रतीत होती है, जबकि जांच वाले दिन गुणवत्ता बेहतर रहने की बात कही,हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

मिलीभगत के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं...

रेड्डी ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में विभागीय स्तर से लेकर अन्य संबंधित पक्षों के बीच कथित मिलीभगत के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उनका कहना है कि यदि शिकायतों की निष्पक्ष और गोपनीय जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है,उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण और निगरानी तंत्र की कमजोरी के कारण शराब दुकानों में अनियमितताओं की आशंका बनी रहती है।

शराब दुकानों के स्थान चयन पर भी उठाए सवाल

पूर्व महापौर ने केवल मिलावट के आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि शराब दुकानों के संचालन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए,उनका कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों और मुख्य सड़कों के किनारे शराब दुकानों का संचालन सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, उन्होंने सरकार से मांग की कि शराब दुकानों के संचालन संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा आवश्यक होने पर संवेदनशील क्षेत्रों से दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

उच्चस्तरीय जांच की मांग...

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार एवं आबकारी विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए,यदि जांच में मिलावट,अनियमितता अथवा किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों,कर्मचारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए,उन्होंने यह भी मांग की कि चिरमिरी शहर में कथित रूप से अवैध एवं मिलावटी शराब के कारोबार पर स्थायी रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

जनता में बढ़ी चर्चा...

शिकायत और उसके बाद हुई विभागीय कार्रवाई के बाद शहर में शराब की गुणवत्ता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, कई लोगों का मानना है कि यदि समय-समय पर अचानक और निष्पक्ष जांच की जाए तो उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

आबकारी विभाग का पक्ष

आबकारी विभाग की ओर से जांच के दौरान किसी भी दुकान अथवा भंडारण स्थल पर मिलावटी शराब मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है,यदि विभाग का विस्तृत पक्ष या जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

एमसीबी के पत्रकार रविकांत सिंह को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित 'समाचार4मीडिया 40 अंडर 40 अवॉर्ड'

राष्ट्रीय स्तर पर खोजी और जनसरोकार की पत्रकारिता को मिला सम्मान,28 जुलाई को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में होगा सम्मान समारोह

यूनिसेफ मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अवॉर्ड से पहले ही हो चुके हैं सम्मानित, अब देश के टॉप-40 युवा पत्रकारों में बनाई जगह

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के युवा एवं निर्भीक पत्रकार रविकांत सिंह राजपूत को देश के प्रतिष्ठित 'समाचार 4 मीडिया 40 अंडर 40 अवॉर्ड 2026' के लिए चयनित किया गया है,यह सम्मान देशभर के उन चुनिंदा पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने 40 वर्ष से कम आयु में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य,जनसरोकार,नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है,आगामी 28 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित भव्य समारोह में रविकांत सिंह राजपूत को इस राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। उनके चयन से न केवल एमसीबी जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में हर्ष का माहौल है।

कड़े मानकों और विशेषज्ञ जूरी की कसौटी पर चुने गए देश के टॉप- 40 युवा पत्रकार-'समाचार4मीडिया 40 अंडर 40 अवॉर्ड' भारतीय मीडिया जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल है, इस सम्मान के लिए प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया से जुड़े देशभर के 40 वर्ष से कम आयु के पत्रकारों का चयन किया जाता है, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक प्रभाव छोड़ा हो, इस वर्ष चयन प्रक्रिया अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक रही। देश के वरिष्ठ संपादकों, मीडिया विशेषज्ञों और अनुभवी पत्रकारों की उच्चस्तरीय जूरी ने विभिन्न मापदंडों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया,खोजी पत्रकारिता,जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने,नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव जैसे पहलुओं को आधार बनाकर चयन किया गया। रविकांत सिंह राजपूत ने अपनी जमीनी रिपोर्टिंग और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर लगातार किए गए कार्यों के दम पर देश के शीर्ष 40 युवा पत्रकारों में स्थान बनाया।

दिल्ली में सजेगी मीडिया जगत की दिग्गज हस्तियों की महफिल-पुरस्कार समारोह 28 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सेमिनार हॉल में आयोजित होगा,समारोह में देश के प्रतिष्ठित संपादक,मीडिया संस्थानों के प्रमुख, वरिष्ठ पत्रकार और संचार जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी,अवॉर्ड समारोह से पहले सुबह 10 बजे विशेष मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा,जिसमें मीडिया के बदलते स्वरूप,डिजिटल पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फेक न्यूज की चुनौती और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश के शीर्ष पत्रकार अपने विचार साझा करेंगे।

ग्राउंड रिपोर्टिंग से बनाई अलग पहचान-रविकांत सिंह राजपूत ने अपनी पत्रकारिता के दौरान हमेशा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी है,उन्होंने सुदूर वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य,आदिवासी समाज,बच्चों के अधिकार, प्रशासनिक लापरवाही,भ्रष्टाचार और सामाजिक समस्याओं पर लगातार प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है,उनकी कई रिपोर्टों के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और अनेक समस्याओं का समाधान भी हुआ,विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को पुनः संचालित कराने,अंधविश्वास के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने तथा शोषित एवं वंचित वर्ग की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने में उनकी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

यूनिसेफ से भी मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान- रविकांत सिंह इससे पहले यूनिसेफ के प्रतिष्ठित 'मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अवॉर्ड' से भी सम्मानित हो चुके हैं, यह सम्मान उन्हें बच्चों के अधिकार,ग्रामीण शिक्षा, बाल संरक्षण और संवेदनशील सामाजिक विषयों पर उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया गया था, यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान द्वारा सम्मानित होने के बाद अब 'समाचार4मीडिया 40 अंडर 40 अवॉर्ड' से सम्मानित होना उनके पत्रकारिता जीवन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि उनकी पत्रकारिता केवल समाचारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम भी बनी।

यह सम्मान आम लोगों के संघर्ष को समर्पित- अपनी इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए रविकांत सिंह राजपूत ने कहा कि 'यूनिसेफ के बाद अब समाचार4मीडिया का यह राष्ट्रीय सम्मान मिलना मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है,यह पुरस्कार उन आम लोगों के संघर्ष, उम्मीदों और विश्वास को समर्पित है, जिनकी आवाज को मैंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से मंच देने का प्रयास किया, वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन,सहयोगियों के समर्थन और समाज के विश्वास के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी,उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक जिम्मेदारी, निष्पक्षता तथा जनसरोकार की पत्रकारिता करने की प्रेरणा देगा।

छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण

रविकांत सिंह राजपूत का देश के प्रतिष्ठित 'समाचार4मीडिया 40 अंडर 40 अवॉर्ड' के लिए चयन होना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के लिए भी गर्व का विषय है,सीमित संसाधनों के बीच जमीनी मुद्दों पर की गई उनकी निर्भीक और जनपक्षीय पत्रकारिता को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी,28 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाला सम्मान समारोह उनके पत्रकारिता जीवन में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है।

CMYK

ऐल्फा की नाक में दम करेगा राव बहादुर

महेश बाबू की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर आउट,लास्ट सीन तक बंधे रहेंगे आप...

महेश बाबू की मोस्ट अवेटेड फिल्म राव बहादुर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है,जो सस्पेंस से भरपूर है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस मैदान में ऐल्फा को टक्कर देने के लिए उतर रही है। महेश बाबू अगले साल प्रियंका चोपड़ा के साथ एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी से बड़े पर्दे पर धूम मचाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि,उससे पहले ही अभिनेता ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। महेश बाबू और नम्रता शिरोड़कर के प्रोडक्शन हाउस जीएमबी एंटरटेनमेंट बैनर तले बनी फिल्म राव बहादुर का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसमें कूट-कूटकर सस्पेंस भरा हुआ है। जो न सिर्फ ऑडियंस को खुद को बांधे रखेगी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ऐल्फा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी।

सस्पेंस से भरा हुआ है राव बहादुरका हर सीन

साउथ के जाने-माने फिल्ममेकर वेंकटेश महा के निर्देशन में बनी इस फिल्म महेश

बाबू ने भले ही एक्ट न किया हो,लेकिन ट्रेलर के शुरुआती सीन में ही उन्होंने जिस तरह से नेरेशन दिया, उनकी आवाज ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। राव बहादुर के ट्रेलर की शुरुआत में नेरेशन देते हुए महेश बाबू कहते हैं ड्रामा लॉजिक को नहीं मानता, जब ड्रामा मैजिक से मिलता है, तो लॉजिक के अपने मायने ही बदल जाते हैं।
जैसे-जैसे मूवी का ट्रेलर आगे बढ़ता है, उसमें इस चीज को बखूबी उतारा गया है कि कैसे एक शक सभी की जिंदगियों को बदलकर रख सकता है। साइकोलॉजिकल फिल्म का ये ट्रेलर लोगों को लास्ट सीन तक जकड़ कर रखता है।

आलिया भट्ट की एल्फा से होगी राव बहादुर की टक्कर

महेश बाबू के प्रोडक्शन में बनी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी में वर्सेटाइल एक्टर सत्यदेव मुख्य किरदार निभा रहे हैं। अब अगर आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि ऐल्फा से साउथ सिनेमा की फिल्म राव बहादुर का क्या लेना-देना है, वह हिंदी फिल्म है और महेश बाबू की साउथ मूवी।
हम आपको बता दें कि वॉर 2 की तरह ही यशराज फिल्म्स आलिया भट्ट शरवरी वाघ और बॉबी देओल स्टारर ऐल्फा को साउथ में रिलीज करने जा रहे हैं। हालांकि, उनके सामने अब राव बहादुर फिल्म खड़ी है, जो 3 जुलाई 2026 को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अनोखे सॉंग ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

हिंदी सिनेमा में गानों का हमेशा से ही खास महत्व रहा है। कई बार फिल्में अपने संगीत की वजह से ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो जाती हैं। पुराने दौर से लेकर आज तक ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जहां गानों ने फिल्मों को हिट बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा भी अनोखा गाना मौजूद है, जो अपने लिरिक्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी खास बनावट के कारण चर्चा में रहा। यह गाना किसी सामान्य गीत की तरह नहीं लिखा गया था, बल्कि इसे 60 अलग-अलग फिल्मों के टाइटल्स को जोड़कर तैयार किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने में पारंपरिक अर्थों में कोई लिरिक्स नहीं थे, फिर भी यह अपने समय का बेहद लोकप्रिय और चर्चित गीत बन गया। फिल्मी जानकारों के अनुसार, इस अनोखे प्रयोग ने दर्शकों को हैरान भी किया और मनोरंजन भी दिया। गाने में इस्तेमाल किए गए फिल्मी टाइटल्स को इस तरह से पिरोया गया था कि वह एक प्रवाहपूर्ण गीत जैसा महसूस होता था। श्रोताओं को शुरुआत में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह वास्तव में अलग-अलग फिल्मों के नामों का संयोजन है। बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी भले ही सैड एंडिंग पर खत्म होती है,लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के गानों और कहानी ने मिलकर दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा,जिसके कारण यह लंबे समय तक चर्चा में बनी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रयोग उस समय के फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक सोच को दर्शाता है। बिना पारंपरिक गीत लेखन के, केवल फिल्मी नामों को जोड़कर एक ऐसा गाना तैयार करना एक साहसिक कदम था,जिसे दर्शकों ने भी स्वीकार किया। यह फिल्म इस बात का उदाहरण मानी जाती है कि अगर कंटेंट और प्रस्तुति मजबूत हो तो किसी भी प्रयोग को दर्शकों का प्यार मिल सकता है। गाने की लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया कि मनोरंजन की दुनिया में नवाचार हमेशा लोगों को आकर्षित करता है।

क्वीन 2 के लिए मिल गया लीड हीरो,कंगना रनौत की फिल्म में नजर आएगा ये एक्टर?

अभिनेत्री कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म क्वीन 2 के लीड एक्टर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत का नाम लंबे समय से फिल्म क्वीन 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। क्वीन 2 की शूटिंग का समापन हाल ही में हुआ है, जिसकी जानकारी मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किए गए रैप अप वीडियो के जरिए मिली। अब खबर आ रही है कि क्वीन 2 के लिए लीड एक्टर की तलाश भी खत्म हो गई है,जो कंगना के अपोजिट नजर आएगा। वह कौन सा कलाकार है, जो क्वीन 2 में नजर आएगा।

क्वीन 2 में नजर आएगा ये एक्टर

भारत भाग्य विधाता के बाद कंगना रनौत फिल्म क्वीन 2 में नजर आएंगी। जिसका डायरेक्शन विकास बहल कर रहे हैं,जो अजय देवगन की शैतान जैसी कई सफल

फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि क्वीन 2 में कंगना के साथ कौन से एक्टर काम करता हुआ दिखेगा।
इसका पुष्टिकरण हो गया है और ई टाइम्स की रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है कि सुबोध भावे वह कलाकार हैं, जो क्वीन 2 में लीड एक्टर बनेंगे।
दरअसल क्वीन 2 की शूटिंग पूरी होने के खुशी में मेकर्स ने सेट पर एक रैप अप सेलिब्रेशन किया, जिसमें फिल्म की लीड कास्ट और निर्देशक नजर आए। इस दौरान कंगना रनौत निर्देशक विकास बहल को केक खिलाती हुई दिखाई दीं और उनके साथ मराठी सिनेमा के मशहूर कलाकार सुबोध भावे भी नजर आए।इससे ये साफ हो गया है कि सुबोध ही क्वीन 2 के लीड एक्टर हैं, जो कंगना संग बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। ये पहला मौका होगा जब सुबोध और कंगना किसी भी फिल्म के लिए एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।

मराठी फिल्मों के लिए मशहूर हैं सुबोध भावे

दरअसल सुबोध भावे मराठी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने मराठी टीवी इंडस्ट्री से लेकर बड़े पर्दे तक अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है।

स्ट्रगल के बाद माधुरी दीक्षित ने बनाई बॉलीवुड में पहचान

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। अपनी शानदार अदाकारी, बेहतरीन डांस और मुस्कान के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके करियर की शुरुआत एक ऐसी फिल्म से हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। माधुरी दीक्षित ने 10 अगस्त 1984 को रिलीज हुई फिल्म 'अबोध' से बॉलीवुड में कदम रखा। उस समय उनकी उम्र करीब 15 से 16 वर्ष थी। खास बात यह रही कि उन्हें इस फिल्म का प्रस्ताव घर बैठे ही मिला था। उस दौर में उन्होंने अभिनय को करियर बनाने की योजना नहीं बनाई थी और न ही फिल्मों में आने का कोई विशेष सपना देखा था।
बताया जाता है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान फिल्म निर्माताओं ने उन्हें मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'अबोध' से अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्देशन हीरेन नाग ने किया था, जबकि उनके साथ बंगाली अभिनेता तापस पॉल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी गौरी नाम की एक मासूम और कम उम्र की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है,जिसकी शादी जल्दी हो जाती है। शादी के बाद वह धीरे-धीरे रिश्तों,जिम्मेदारियों और वैवाहिक जीवन को समझने लगती है। हालांकि कहानी को सराहना मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को आकर्षित नहीं कर सकी और व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही।
पहली फिल्म के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बावजूद माधुरी दीक्षित ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और बाद के वर्षों में कई सफल फिल्मों के जरिए अपनी पहचान मजबूत की। उनके अभिनय और नृत्य कौशल ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। अपने करियर में माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड के तीनों प्रमुख खान–शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान–के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। इन कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने

खूब पसंद किया और उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। आज भी माधुरी दीक्षित फिल्म और मनोरंजन जगत का एक बड़ा नाम हैं। दशकों लंबे करियर के बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है और वह फिल्मों, टेलीविजन तथा अन्य मंचों पर लगातार सक्रिय नजर आती हैं। उनका सफर इस बात का उदाहरण माना जाता है कि शुरुआती असफलता के बाद भी लगातार मेहनत और समर्पण से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है।

आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे से टीवी इंडस्ट्री में हलचल

टेलीविजन जगत में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब आकांक्षा चमोला ने अभिनेता गौरव खन्ना से अपने तलाक को लेकर सार्वजनिक रूप से बड़ा खुलासा किया। इस अनाउंसमेंट के बाद से सोशल मीडिया और टीवी इंडस्ट्री में लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं और दोनों के निजी जीवन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों और हालिया खुलासों के मुताबिक, यह दावा किया जा रहा है कि गौरव खन्ना को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आकांक्षा चमोला इतनी बड़ी घोषणा सार्वजनिक मंच पर करेंगी। इस खुलासे ने इस पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया है।
बताया जा रहा है कि यह बयान नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप' में दिया गया, जिसके बाद से यह मामला चर्चा में आ गया। शो के दौरान दिए गए इस अनाउंसमेंट ने न सिर्फ दर्शकों को चौंकाया, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों को भी हैरान कर दिया।
इसी बीच टेलीविजन अभिनेता अनुज सचदेवा ने विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि गौरव और आकांक्षा पिछले लगभग नौ महीनों से एक साथ नहीं रह रहे थे। अनुज सचदेवा ने बातचीत में बताया कि शो में आकांक्षा के बयान के बाद उन्होंने गौरव खन्ना से इस पूरे मामले पर बात की थी। उनके अनुसार, गौरव इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आकांक्षा सार्वजनिक मंच पर इस तरह का खुलासा करेंगी। यह भी सामने आया है कि इस अनाउंसमेंट के बाद गौरव खन्ना काफी हैरान रह गए और उन्हें स्थिति को समझने में समय लगा। बताया जा रहा है कि निजी रिश्तों से जुड़ी इतनी बड़ी जानकारी सार्वजनिक होने से दोनों के करीबी लोग भी आश्चर्य में हैं।
टीवी इंडस्ट्री में इस खबर के सामने आने के बाद से ही चर्चाओं का दौर जारी है। कई लोग इसे निजी जीवन से जुड़ा संवेदनशील मामला मानते हुए सार्वजनिक मंच पर इस तरह के खुलासे को लेकर अलग-अलग राय रख रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग आकांक्षा के फैसले को उनकी व्यक्तिगत पसंद बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे निजी रिश्तों की गोपनीयता से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे स्थिति और अधिक अस्पष्ट बनी हुई है। हालांकि टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्टता सामने आ सकती है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रियलिटी शो और सार्वजनिक मंचों पर निजी जीवन से जुड़े खुलासे करना सही है या नहीं। इंडस्ट्री के कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं और इसे एक संवेदनशील विषय बता रहे हैं। कुल मिलाकर, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक को लेकर हुआ यह खुलासा टीवी इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और इस पर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं।

खेल समाचार

वर्ल्ड कप जीत ने जगाया देश के लिए खेलने का सपना: शेडगे

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। सूर्यांश शेडगे ने बताया कि 2011 में भारत की विश्व कप जीत ने उनके अंदर देश के लिए खेलने का सपना जगाया। उन्होंने कहा कि भारत की जीत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसी पल उन्होंने तय कर लिया था कि वह एक दिन भारत के लिए खेलेंगे और सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने के बाद सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। इसके बाद उन्होंने रविवार को स्टॉर्मोंट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत के लिए डेब्यू किया। भारतीय टीम में चयन के बाद अपनी यात्रा पर बात करते हुए सूर्यांश शेडगे ने उस पल को याद किया, जिसने उनके अंदर देश के लिए खेलने का सपना जगाया। उन्होंने बताया कि 2011 में भारत की विश्व कप जीत ने उन पर गहरा असर डाला और तभी उन्होंने एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प लिया। शेडगे ने कहा, क्रिकेट देखते हुए मैं पहली बार तब रोया था, जब भारत ने 2011 का विश्व कप जीता था। उस रात भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाते देखकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। तभी मैंने तय कर लिया कि मुझे भी एक दिन सबसे बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। उसी दिन से मैंने इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी।
शेडगे ने जियोस्टार से कहा, मुझे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार था। जब पहली बार मैंने भारतीय टीम

की जर्सी पहनी, तो उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सुबह जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना और कई त्याग करना, उस पल सब कुछ सफल लगा। बचपन से मैंने इसी दिन का सपना देखा था। भारतीय जर्सी पहनना मेरे लिए सिर्फ सपना पूरा होने जैसा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने चयन की आधिकारिक घोषणा होने के बाद प्राप्त हुई पहली बधाई कॉलों में से एक को भी याद किया और बताया कैसे उनकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ भावनात्मक बातचीत हुई थी।

चंडीगढ़ की क्रिकेटर 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम में चुनी गईं

चंडीगढ़,01 जुलाई 2026। यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक और गर्व की बात यह है कि चंडीगढ़ की क्रिकेटर नंदिनी शर्मा को 2026 एशियन गेम्स के लिए इंडियन विमेंस टीम में चुना गया है। ये गेम्स सितंबर में जापान के आइची-नागोया में होने वाले हैं। इंडियन विमेंस टीम 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक चीन के हांग्जो में हुए पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस कॉम्पिटिशन में उतरेगी।
नंदिनी को अलग-अलग डोमेस्टिक और

नेशनल कॉम्पिटिशन में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए इनाम मिला है। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने एसीसी राइजिंग स्टार विमेंस एशिया कप में इंडिया, को रिप्रेजेंट किया, जिससे उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर काफी पहचान मिली। बीसीसीआई द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर लेवल के टूर्नामेंट में पंजाब और यूटीसीए दोनों को रिप्रेजेंट करने के बाद,नंदिनी ने सीनियर विमेंस इंटर-जोनल टूर्नामेंट, विमेंस टी 20 चैलेंजर ट्रॉफी और सीनियर विमेंस वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी सहित बड़े डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स विमेन के साथ उनके जुड़ाव ने भी हाईएस्ट लेवल पर उनके डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई। लीग में उनके परफॉर्मेंस ने दुनिया के कुछ बड़े क्रिकेटरों के खिलाफ मुकाबला करने की उनकी काबिलियत दिखाई और बाद में इंग्लैंड के लिए चल रहे वर्ल्ड कप टी 20 इंडियन स्क्वाड में उनकी जगह पक्की की। अपनी खुशी जाहिर करते हुए, यूटीसीए प्रेसिडेंट सारांश टंडन ने कहा, ÷एशियन गेम्स के लिए इंडियन टीम में नंदिनी का सिलेक्शन चंडीगढ़ और यूटीसी के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने इतने सालों में अपने डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लगातार परफॉर्मेंस से यह मौका हासिल किया है। हमें यकीन है कि वह इंडियन टीम में अहम योगदान देंगी और इस इलाके के युवा क्रिकेटरों को इंस्पायर करती रहेंगी।÷

विश्वनाथ और चंद्रिका के कंधों पर भारतीय टीम का दारोमदार

नई दिल्ली,01 जुलाई 2026। भारत -19 और -23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अनुभवी खिलाड़ियों और उभरते हुए टैलेंट का बैलेंस्ड मिक्स उतारेगा। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका भोरेश पुजारी इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में देश की चुनौती को लीड करेंगे। यह इवेंट 3 जुलाई से इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू होगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को दोनों एज ग्रूप्स के लिए अपनी टीमों की घोषणा की।

CMYK

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़,युवाओं को कौशल,रोजगार और नवाचार के मिलेंगे नए अवसर : सीएम साय

रायपुर,01 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास एवं विस्तार,मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई-प्रगति पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम),सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स एवं विभिन्न डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने एवं तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं,बल्कि सुशासन,पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है,बल्कि प्रदेश के लोगों को एआई के लिए तैयार करना,व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आय में वृद्धि करना तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि,कौशल विकास और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में एआई के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य में मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा सुरक्षित,विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में प्रस्तुत विजन दस्तावेज में बताया गया कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में एआई सीख सके,सरकार तकनीक आधारित भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे और उद्योगों तथा व्यवसायों को नई गति मिले। इस मिशन के अंतर्गत पांच प्रमुख स्तंभों - एआई कौशल विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप, जागरूकता एवं आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई तथा शासन में एआई के उपयोग पर कार्य किया जाएगा।

विद्यार्थियों,सरकारी कर्मचारियों को एआई का मिलेगा प्रशिक्षण

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, एआई एवं रोबोटिक्स क्लब तथा हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम,छात्र परियोजनाओं के लिए अनुदान,आईटीआई में एआई लैब तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब्स,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस,एआई आधारित स्टार्टअप,डेटा सेट तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा,सीड फंडिंग तथा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की भी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तर पर एआई नीति की जाएगी तैयार

बैठक में सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई उपयोग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर एआई नीति तैयार की जाएगी,जिसमें डेटा सुरक्षा,नागरिकों की निजता का संरक्षण,नियमित तकनीकी ऑडिट तथा केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शासन में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, प्रत्येक विभाग का अलग रोडमैप तैयार होगा,एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी एआई पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सरल,सुलभ और समावेशी बन सकें।

ढाई सालों में एक हजार मोबाइल टॉवर स्थापित

बैठक में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में डीबीएन वित्तपोषित लगभग एक हजार मोबाइल टॉवर स्थापित कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त 577 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 406 टावरों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 171 प्रकरणों का निराकरण आगामी एक माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सेवा सेतु पोर्टल में 36 विभागों की 520 सेवाएं उपलब्ध

सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में राज्य के 36 विभागों की 520 सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें 111 होस्टेड तथा 409 रीडायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। प्रदेशभर में संचालित 16 हजार 726 सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु के माध्यम से 39 .75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं,जिनमें से 37 .52 लाख आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए 94 .3 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेवा सेतु में क्यूआर आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन,आधार प्रमाणीकरण, डिजिलॉकर एकीकरण, ट्रेजरी एवं ई-चालान प्रणाली तथा डीबीटी आधारित भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे सेवाओं की पारदर्शिता,विश्वसनीयता और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

छत्तीसगढ़ में कमिश्नर हटाने का प्रस्ताव रद्द हाईकोर्ट ने कहा-बहुमत नहीं,कानून सर्वोपरि

बिलासपुर,01 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में बहुमत कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून और तय प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकता। इसी के साथ हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम के 32 पार्षदों की याचिका खारिज कर दी,जिसमें निगम कमिश्नर को हटाने के प्रस्ताव को लागू करने की मांग की गई थी। यह पूरा विवाद भिलाई नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों और कमिश्नर के बीच प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों को लेकर लंबे समय से चल रहे टकराव से जुड़ा है। पार्षदों का आरोप था कि कमिश्नर राजीव पांडेय बिना मेयर-इन-काउंसिल और

सामान्य सभा की मंजूरी के कई वित्तीय निर्णय ले रहे थे और पारित प्रस्तावों को लागू नहीं किया जा रहा था। मामला तब और बढ़ गया जब 25 मार्च 2026 को नगर निगम की विशेष बजट बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्षदों ने अचानक नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 54(2) का हवाला देते हुए कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। पार्षदों ने दावा किया कि इस प्रस्ताव को तीन-चौथाई बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि स्थानीय निकायों को संविधान के तहत स्वायत्तता प्राप्त है और जब निर्वाचित सदस्यों का भारी बहुमत किसी अधिकारी पर अविश्वास जताता है तो सरकार को उसे हटाना ही चाहिए। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की सामूहिक इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य सरकार की ओर से उप-महाधिवक्ता ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि नगर निगम की विशेष बैठक केवल बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी।

नकटी गांव के ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट... बोले...ईडब्ल्यूएस मकानों में नहीं रहना चाहते

कांग्रेस एमएलए बोलीं...गरीबों का घर उजाड़कर विधायक आवास नहीं चाहिए...

रायपुर,01 जुलाई 2026। रायपुर के नकटी गांव में सोमवार को विधायक कॉलोनी बनाने नकटी गांव में 80 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब इसके विरोध में बुधवार को प्रभावितों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि प्रशासन ने घर दिए हैं, जिनमें किसी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। घर इतने छोटे हैं कि उसमें परिवार का रह पाना संभव नहीं है। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की और उन्हें समझाइश दी, लेकिन फिर भी वे डटे हुए हैं। इस प्रदर्शन में रायपुर जिला कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। वहीं,कांग्रेस विधायक जनकराम ध्रुव और चातुरीनंद के बाद कविता लहरे ने भी नकटी गांव विस्थापन के विरोध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक चातुरीनंद ने कहा कि हम जनता के सिर पर छत देने के लिए चुने गए हैं,छीनने के लिए नहीं। गरीबों का घर उजाड़कर ऐसा विधायक आवास बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अलावा नकटी गांव को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी एक साल पुरानी चिट्ठी वायरल हो रही है। जिसमें उन्होंने विधायक कॉलोनी के लिए जमीन चयन पर आपत्ति जताई थी। पत्र में कहा था कि गरीबों को हटाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है।

विधायक कॉलोनी दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग...

सरायपाली से कांग्रेस विधायक चातुरीनंद ने नकटी गांव तोड़ने के विरोध में सीएम साय को पत्र लिखा है। उन्होंने नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाने की योजना वापस लेने या नया रायपुर में कहीं कॉलोनी को शिफ्ट करने की मांग की है। विधायक ने इस पूरी घटना को अत्यंत पीड़ादायक,अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

गरीबों का घर उजाड़कर विधायक आवास नहीं चाहिए...

चातुरीनंद ने पत्र में लिखा है कि, गरीबों का आशियाना उजाड़कर जनप्रतिनिधियों के लिए आलीशान आवास बनाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। जनता ने हमें उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए चुना है, न कि उनके सिर से छत छीनकर अपने लिए सुविधाएं खड़ी करने के लिए। मैं इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करती हूं और नकटी गांव के सभी पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी हूं। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि, गरीबों का घर उजाड़कर उन्हें ऐसा विधायक आवास बिल्कुल नहीं चाहिए।

कोर्ट जाएगी कांग्रेस : नया रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर चलाने पर घिरे बैज, बोले-पार्टी गांव वालों के साथ

राजधानी रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 29 जून को प्रशासन ने गांव में वर्षों से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बारिश के पहले बेघर कर दिया। कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और आगामी विधानसभा मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। श्री बैज ने कहा कि नकटी गांव में कई परिवार 20 से 40 वर्षों से निवास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना घरों को तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान 85 प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास भी ध्वस्त कर दिए गए। बैज ने कहा कि ग्रामीण अपने मकान बचाने के लिए रोते-बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए गरीबों के घर तोड़े गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नया रायपुर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, तो वहां कॉलोनी बनाने के बजाय गरीबों को उजाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुनर्वास से पहले प्रभावित लोगों से कोई संवाद नहीं किया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी...लंबे लिव-इन के बाद शादी से इनकार करना हर मामले में दुष्कर्म नहीं

बिलासपुर,01 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के आरोपी को बरी करने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि दो बालिग लंबे समय तक अपनी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहे हों, तो बाद में शादी से इनकार कर देने मात्र से दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की डिवीजन बेंच ने कहा कि आज के समय में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने में सक्षम हैं। ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के आचरण और रिश्ते की प्रकृति को भी देखा जाना जरूरी है। अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का भी हवाला दिया। मामला वर्ष 2019 का है। 40 वर्षीय महिला ने आईआईएम रायपुर के एमबीए कार्यक्रम में दाखिला लिया था, जहां उसकी मुलाकात एक सहपाठी से हुई। महिला का आरोप था कि 5 जुलाई 2019 को आरोपी ने पढ़ाई के बहाने उसे अपने घर बुलाया और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए।

बिलासपुर हाईकोर्ट का नया रोस्टर : 3 जुलाई से बदल जाएगी सुनवाई की व्यवस्था,मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं

बिलासपुर,01 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नया रोस्टर यानी जजों की बैठकों और मामलों की सुनवाई की नई व्यवस्था जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। नए रोस्टर के अनुसार अलग-अलग डिवीजन बेंच यानी दो जजों की पीठ और सिंगल बेंच यानी एक जज की पीठ के बीच मुकदमों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के काम भी तय कर दिए गए हैं। नए नियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बड़ी बेंच जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगी। जनहित याचिका का मतलब ऐसे मामलों से होता है जिससे समाज के एक बड़े हिस्से का भला जुड़ा हो। इसके अलावा यह बेंच बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने का मामला,गंभीर आपराधिक अपील, फांसी की सजा से जुड़े मामले, कोर्ट की अवमानना और एफआईआर निरस्त करने जैसी जरूरी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की दो जजों वाली बेंच को वे सभी आपराधिक मामले सौंपे गए हैं जो किसी दूसरी बेंच के पास नहीं हैं। वहीं जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच साल दो हजार सोलह से रुके हुए दोषमुक्ति यानी कोर्ट से बरी किए गए मामलों के खिलाफ आई अपीलों को सुनेगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच को सिविल मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। यह बेंच शादी-ब्याह और परिवार से जुड़े मुकदमों की पहली अपील,टैक्स यानी कर से जुड़े मामले,अलग-अलग ट्रिब्यूनल यानी विशेष अदालतों के फैसलों के खिलाफ आई याचिकाओं और व्यापारिक विवादों से जुड़े कमर्शियल मामलों की सुनवाई करेगी।

छत्तीसगढ़ में 5 जुलाई से राशन दुकानें होंगी बंद...13 हजार दुकानों पर लग सकता है ताला,70 लाख हितग्राही होंगे प्रभावित

रायपुर,01 जुलाई 2026। प्रदेश के राशन दुकान संचालकों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अगर सरकार से सहमति नहीं बनी तो राज्य की करीब 13 हजार उचित मूल्य की दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लगभग 70 लाख राशन कार्डधारकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। राशन विक्रेताओं का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद वर्षों से पुराने मानकों पर ही कमीशन मिल रहा है। मौजूदा मार्जिन से दुकान का किराया, स्टाफ का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्च निकालना मुश्किल है। इसलिए मार्जिन राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग है।

बीमा और झूठे मामलों पर रोक की मांग : अन्य मांगों में शक्कर वितरण पर कमीशन बढ़ोतरी, राशन विक्रेताओं के लिए बीमा सुविधा, स्टॉक सत्यापन प्रक्रिया सरल करना और तकनीकी खामियों का समाधान शामिल है। साथ ही राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में दर्ज होने वाले कथित झूठे मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई है। संचालकों ने आरोप लगाया कि नवंबर 2025 से मार्जिन मनी का भुगतान लंबित है। बारदाना और आधार आधारित वितरण की राशि भी समय पर नहीं मिल रही। कई संचालकों को उधार लेकर दुकान चलानी पड़ रही है। एक साथ कई महीनों का राशन बांटने और नई परिवहन प्रणाली से दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक अनाज रखना भी चुनौती है। तौल में अंतर से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी मांगी गई है। राशन दुकान संचालक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो 5 जुलाई से प्रदेशभर में राशन वितरण ठप हो सकता है।

जिलाध्यक्ष कांग्रेस विधायकों की लोकप्रियता का करेंगे सर्वे बनेगा रिपोर्ट कार्ड,जिलाध्यक्षों के कामकाज पर रेड-येलो-ग्रीन रेटिंग

रायपुर,01 जुलाई 2026। दस दिन तक चले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में संगठन को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। अब जिलाध्यक्षों के कामकाज का मूल्यांकन रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी में किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अपने-अपने जिले के कांग्रेस विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने और जनता के बीच उनकी छवि को लेकर सर्वे कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। पार्टी के मुताबिक ग्रीन कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्ष, येलो कैटेगरी में सुधार की जरूरत वाले और रेड कैटेगरी में कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्ष रखे जाएंगे। इसी आधार पर संगठन उनकी कार्यशैली की समीक्षा करेगा। प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। इसके लिए जनता के बीच जाकर यह भी पता लगाया जाएगा कि विधायक के कामकाज को लेकर लोगों की क्या राय है। संगठन इस फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगा।

मेघा महानदी पुल हादसा : 12 टन का गर्डर गिरा,46.97 करोड़ की परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल

धमतरी,01 जुलाई 2026। महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी और ओडिशा को जोड़ने वाले मेघा महानदी पुल के निर्माण में बड़ा हादसा हो गया। यहां दो हैवी क्रेन से चढ़ाते समय 10-12 टन वजनी गर्डर गिरकर कई टुकड़ों में टूट गया। 46.97 करोड़ की इस परियोजना की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शहरऔर स्थानीय मार्गदर्शिका

मलबा दबाने का आरोप, जांच की मांग : जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गर्डर टूटने के बाद मलबे को मशीनों से दबाकर जमीन में मिलाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि अगर निर्माण मानकों के अनुरूप होता तो क्षतिग्रस्त गर्डर को जांच के लिए सुरक्षित रखा जाता। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

तकनीकी निगरानी में लापरवाही का आरोप : क्षेत्रवासियों का आरोप है कि हादसे के समय तकनीकी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे और महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी में लापरवाही बरती गई। यह पुल भविष्य में हजारों वाहनों का भार उठाएगा, इसलिए निर्माण गुणवत्ता से समझौता बड़े खतरे को जन्म दे सकता है। पुल का निर्माण कार्य 8 जनवरी 2025 से चल रहा है।

डायवर्सन रोड भी बना मुसीबत : पुल निर्माण में देरी के साथ डायवर्सन मार्ग की खराब हालत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार साढ़े पांच करोड़ की स्वीकृति के बावजूद लंबे समय तक सड़क नहीं बनी। बाद में मिट्टी-मुरूम डालकर बनाई गई अस्थायी सड़क बारिश में खराब हो गई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)